तृतीय माला, खण्ड १५—अंक २६

शनिवार, २३ मार्च, १९६३
२ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	२५१९–२२
(१) जमुरिया कोयला खान में हुई दुर्घटना	
(२) तिब्बत में चीनी सेनाओं का भारी जमाव	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२५२२
प्राक्कलन समिति	२५२३
तीसवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य	२५२३—४०
अनुदानों की मांगें	२५२३
शिक्षा मन्त्रालय	
श्री विश्राम प्रसाद	२५२३–२६
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा	२५२६
श्री मोहसिन	२५२६–२७
श्रीमती लक्ष्मी बाई	२५२७—३०
श्री बैरो	२५३०–३१
श्री रणजंय सिंह	२५३१–३२
श्री अ० त्रि० शर्मा	२५३२—३४
श्री प्र० र० चक्रवर्ती	२५३४–३५
डा० का० ला० श्रीमाली	२५३५—४०
वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय	२५४१—६६
श्री प्रभात कार	२५४१–४२
डा० मेलकोटे	२५४२
श्री बड़े	२५४३—४५
श्री श्याम लाल सर्राफ	२५४५–४६
श्रीमती गायत्री देवी	२५४६
श्री करुथिरमण्	२५४६–४७
श्री हेम बरुआ	२५४७—४९

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख्य पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, २३ मार्च, १९६३
२ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

जमुरिया कोयला खान में दुर्घटना

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं श्रम और रोजगार मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हुं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"२१ मार्च १९६३ को जमूरिया कोयला खान में हुई दुर्घटना जिसके फलस्वरूप छः मजदूरों की मृत्यु हो गयी और कई अन्य घायल हुए ।"

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : यह दुर्घटना २१ मार्च १९६३ के १.३० म० पू० पर जमुरिया ए और बी कोयला खान के मोनियानी तह में बिना खम्भ वाले क्षेत्र में लगभग ११ फुट की ऊंचाई से बिना चेतावनी दिये छत के एक खण्ड के गिरने से हुई। छः व्यक्ति मारे गये एक खान सरदार और ५ मजदूर थे । दो टिम्बर मिस्त्रियों और एक मजदूर को गम्भीर घाव आये ।

यह खान आसनसोल में है और इसके स्वामी मैसर्ज़ इकोटेबिल कोल कम्पनी लिमिटेड है। लगभग ६–३० बजे सवेरे उपमुख्य निरीक्षक स्वयं घटनास्थल पर टेलीफोन से सूचना मिलते ही पहुंच गये । अभी तक मलवे के नीचे से लाशों को निकाला नहीं जा सका है । खानों के उपमुख्य निरीक्षक स्वयं दुर्घटना की जांच कर रहे हैं ।

इस खान से २४,००० टन कोयला प्रतिमास प्राप्त होता है । १९०७ व्यक्ति यहां काम करते हैं और १४०० व्यक्तियों को जमीन के नीचे काम करना पड़ता है । इस दुर्घटना का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

†मूल अंग्रेजी में

28 (Ai) LS—1.

†**श्री हेम बरुआ :** क्या खान की छत अब भी कमजोर ही है। क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि इन खानों में प्रबन्ध ठीक हो और ऐसी दुर्घटनायें न हों ?

†**श्री र० कि० मालवीय :** दुर्घटना की जांच हो रही है, और पूरी जानकारी जांच का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर हीं दी जा सकती है।

†**श्री हेम बरुआ :** सहायता कार्य की स्थिति क्या है ?

†**श्री र० कि० मालवीय :** छत तो ठीक ठाक थी।

श्री द्वारकादास मंत्री (भीर) : जो इस प्रकार की दुर्घटनायें दिन प्रतिदिन होती रहती है, उनको देखते हुए क्या सरकार जो लोग हलाक होते हैं उनके आश्रितों को तुरन्त नौकरी देने के लिए कोई संशोधन लाने का विचार कर रही है ?

श्री र० कि० मालवीय : जैसे ही एक्सिडेंट होता है और उसका पता हमें चलता है, उसी समय उनके परिवारों को सहायता दी जाती है। कोल माइन्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन अलग से सहायता देता है और एम्प्लायीज़ से अलग से दिलाया जाता है। इसके साथ साथ जो उनका कम्पेन्सेशन का क्लेम होता है वह भी उन्हें दे दिया जाता है। दुर्घटना के बारे में इतना ही पता चला है कि यह बिना चेतावनी दिये छत के एक खण्ड के गिरने से हुई। और अधिक जानकारी मेरे पास नहीं।

तिब्बत में चीनी सेनाओं का भारी जमाव

†**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि और उनसे निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"तिब्बत में चीनी सेना का कथित भारी जमाव।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री और अणुशक्ति मंत्री** (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १ मार्च, १९६३ को चीन सरकार के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें बताया गया है कि चीन ने स्वेच्छा से समुची भारत-चीन सीमा पर से अपनी सेवनाएं पीछे हटा ली हैं। यह कहा गया है कि चीन द्वारा अभ्यर्थित 'वास्तविक नियन्त्रण की रेखा' के स्थान से २० किलोमीटर पीछे तक सेनाएं हटा ली गई हैं। यह भी दावा किया गया है कि चीनी सेनाएं ८ सितम्बर, १९६२ को अपनी स्थिति से बहुत पीछे हैं।

३ मार्च को चीन के प्रधान मन्त्री से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी सेनाओं के एक पक्षीय पीछे हटने और बातचीत करने का उल्लेख किया। उत्तर में ५ तारीख को उनको एक पत्र भेज दिया गया है जिसमें बताया गया है कि चीन पहले बिना आरक्षण के कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करे, जैसा कि भारत ने किया है, और तभी भारत बातचीत के लिये तैयार हो सकता है।

पिछले पन्द्रह दिनों से चीन से कई नोट प्राप्त हुए हैं जो उत्तेजित भाषा में लिखे हुए हैं। उनमें लगाये गये झूठे आरोपों का भारत ने अपने उत्तरों में खण्डन किया है।

तिब्बत में सेनाओं के और जमा किये जाने, हमारी सीमाओं के साथ और सड़कें बनाए जाने और हमारी सीमाओं के उत्तर में तिब्बती क्षेत्र में चीन सशस्त्र बलों द्वारा तिब्बती ग्रामीणों, पशुओं

†मूल अंग्रेजी में

आदि के अर्जन के बारे में विश्वस्त जानकारी प्राप्त हुयी है । यद्यपि चीनी सेनाएं अपनी कथित वास्तविक नियन्त्रण की रेखा से २० किलोमीटर पीछे हट गयी है, उस तंग पट्टी के परे उनका जमाव जारी है ।

कुछ अन्य बातों से भी हमारे लिये चीन की शान्तिपूर्ण समझौते की इच्छा पर विश्वास करना कठिन हो गया है । चीनी प्रतिरक्षा मन्त्रालय के वक्तव्य के अन्त में एक चेतावनी है कि यद्यपि चीनी सीमान्त गार्ड ७ नवम्बर, १९५९ की वास्तविक नियन्त्रण की रेखा से पीछे हट गये उन्होंने आत्म-रक्षा का अपना अधिकार नहीं छोड़ा । इसके साथ ही मार्शल चेन यी के इस वक्तव्य से कि भारत सरकार के वर्तमान रवैये को देखते हुए भारतीय सेनाएं समय-समय पर उत्तेजनात्मक कार्यवाही करेगी, यह अर्थ निकलता है कि चीनी जब चाहे आक्रमण कर सकेंगे ।

अतः हमें किसी भी सम्भव घटना के लिए तैयार होना है । फिर भी आशा है कि चीन कोलम्बो देशों द्वारा एकमत से रखे गए प्रस्तावों को स्वीकार करेगा तथा कि उनके प्रस्तावों को प्रथम बिना किसी संकोच के स्वीकार किया जायेगा जिससे भारत-चीन सीमान्त मतभेदों को शान्तिमय तरीकों से दूर किया जा सकेगा ।

श्री यशपाल सिंह : तिब्बतकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है और राजनीतिक कर्त्तव्य भी है, और यह हमारे डिफेंस के लिये भी जरूरी है । तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस मामले में तिब्बत की दलाईलामा सरकार को कोई आश्वासन दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलाहिदा सवाल है । इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर): क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे मिलिटरी इंटेलीजेंस की कुछ तरक्की हुई है जो कि पहले तीसरे दरजे की थी ? और दूसरी बात यह है कि अब अगर चीन का हमला हुआ तो क्या हम अपनी हवाई शक्ति का भी प्रयोग करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे बतलाया जा सकता है पहले से कि हवाई शक्ति का प्रयोग करेंगे या नहीं । सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे सकते हैं कि क्या हमारे मिलिटरी इंटेलीजेंस ने इत्तला दी है कि वहां क्या कुछ हो रहा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आम तौर से मिलिटरी इन्टेलीजेंस की इत्तला बतायी नहीं जाती । लेकिन जाहिर है कि जो कुछ मैंने बताया है उसी जरिये से बताया है, और कोई खबर तो हमारे पास नहीं है ।

श्री किशन पटनायक : क्या मिलिटरी इंटेलीजेंस में कुछ तरक्की हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं क्या अर्ज करूं, हमारी तरक्की तो जारी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : तिब्बत में सेनाओं का जमाम के उल्लेख से मैं यह जानना चाहता हूं कि जाने से पहिले चीनी सेना अधिकारियों ने नेफा में इस प्रकार का वातावरण बनाया और लोगों को अपनी तरफ करके यह कहा कि वे उनके विरूद्ध नहीं और फिर भी आयगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसी बातें हमने भी सुनी हैं कि कुछ चीनी अधिकारियों ने ऐसा कहा है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : इस स्थिति में भारत से लगते स्थानों के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम प्रत्येक प्रकार से सचेत हैं । जासूसों का पता लगने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है । उन व्यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गयी है जिनकी वफादारी पर शक था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार अपने निर्णयों पर कायम रहेगी और धमकियों के आगे नहीं झुकेगी । चीनियों की युद्ध क्षमता के बारे में एकत्र की गयी गुप्त जानकारी को प्रकट नहीं किया जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री आज की स्थिति में यह आश्वासन देंगे कि सरकार कोलम्बो प्रस्तावों पर दृढ़ रहेगी और उससे इधर उधर नहीं होगी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं मैं किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकता । हम अपनी बात पर दृढ़ रहेंगे । इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते ।

श्री यशपाल सिंह : हमारे देश की हिफाजत के लिये यह जानना जरूरी है कि हमारी सरहद पर चाइना की एअर फोर्स का आफेंसिव पोटेंशियल क्या है । क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार ने पता लगाया है कि हमारी सरहद पर चाइना ने कितनी एअर फोर्स इकट्ठी कर रखी है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ न कुछ मालूमात तो जमा किया ही करते हैं, लेकिन जो कुछ मालूमात जमा की हैं उनको मैं यहां आपके सामने अर्ज करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं कृष्णा—गोदावरी के जल के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १०२३/६३]

श्रीमती लक्ष्मी बाई उठीं

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या क्यों खड़ी हो रही हैं ?

एक माननीय सदस्य : वह कुछ सवाल पूछना चाहती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उसकी इजाजत अब नहीं दी जा सकती ।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : श्री अ० म० थामस की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १६ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १०२४/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री बासप्पा** (बंगलौर) : मैं सिंचाई और विद्युत् (विद्युत्) मंत्रालय की निम्नलिखित शाखाओं के बारे में प्राक्कलन समिति का तीसवां प्रतिवेदन पेश करता हूं :

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (विद्युत् विभाग)

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार

केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् (विद्युत्)

बोर्ड—विद्युत् अनुसंधान संस्था ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : २५ मार्च, १९६३ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

(१) आज के आदेश पत्र से शेष रहे किसी कार्य के एकक पर विचार।

(२) स्वास्थ्य, सिंचाई और विद्युत्, श्रम और रोजगार, गृह कार्य और निर्माण ,आवास और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा ।

अनुदानों की माँगें—जारी

शिक्षा मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों और उनके संबंध में प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करेगी ।

श्री विश्राम प्रसाद अपना भाषण जारी रखें । उन्होंने ११ मिनट लिये हैं । दो तीन मिनट वे और ले ल ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल साइंटिफिक और टैक्निकल शिक्षा के बारे में बोल रहा था। मैं आज आपके सामने कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग के बारे में कहूंगा। जो कुछ कदम हमारी सरकार ने उठाये हैं वे ठीक हैं फिर भी मैं चाहता हूं कि हर कालिज और हर स्कूल में कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि स्कूलों और कालिजों में एक मिलिटरी ट्रेनिंग का कम्पलसरी कोर्स होना चाहिये जिससे कि चीनी खतरे का सामना करने के लिये हम तैयार रह सकें ।

हरिजन, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के अनुदानों पर मुझे कहना है कि जैसा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट है तथा उनकी सीटों के रिजर्वेशन का ध्यान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्राम प्रसाद]

रखते हुये, उनकी सीटें जो अभी तक पूरी नहीं होती हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुये मैं एजुकेशन मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह के ट्रेनिंग स्कूल आई० ए० एस० के लिये इलाहाबाद और मद्रास में खोल रक्खे हैं, उसी तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स और जगहों में भी खोले जायें ताकि उनके रिजर्वेशन का जो कोटा है वह पूरा हो सके। उनको इस तरह के ट्रेनिंग स्कूल खोलकर प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि जहां भी उनका कोटा पूरा नहीं है वहां वे अपना कोटा पूरा करें। २,२२,६३,००० उनकी आबादी और रिजर्वेशन को ख्याल में रखते हुये बहुत ही कम हैं।

हिन्दी के बारे में मुझे यह कहना है कि संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी को विकसित करना और समृद्ध बनाना भारत सरकार का कर्त्तव्य है। रिपोर्ट के देखने से पता चलता है कि सरकार द्वारा जो कुछ क़दम इस तरफ़ उठाये गये हैं वह बहुत ही शिथिल हैं। आप अगर दरअसल हिन्दी को प्राथमिकता देना चाहते हैं और इसको सही मायनों में राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं तो इसके लिये आपको बहुत आगे तक क़दम उठाना पड़ेगा।

सुना गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाईज़ के लिये हिन्दुस्तान भर में १०० पब्लिक स्कूल खोले जा रहे हैं। इस संबंध में मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिल्ली के मार्डन स्कूल, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। उस स्कूल के बारे में मुझे बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि वहां पर और स्कूलों के मुकाबले में फीस अधिक चार्ज होती है। इसमें मिनिस्टरी के कुछ लोगों का भी हाथ है। ऐक्स्ट्रा क्लासेज पैसा पैदा करने के लिये लगते हैं। सुनने में यह आया है कि उस स्कूल द्वारा जो बहुत से असगंत कारनामे होते हैं उनमें मिनिस्टरी के कुछ लोगों का भी हाथ है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर इस तरह के पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट खोलने जा रही है तो इस स्कूल का इंतजाम ठीक करके इसे दिल्ली के लिये अवश्य देने की कृपा करें।

मैं इस के बाद अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की १९६२ की आठवीं आडिट रिपोर्ट की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। सेंट्रल सोशल वेलफ़ेयर बोर्ड को बने नौ साल हो गये। आडिट की रिपोर्ट है कि उसका कांस्टीट्यूशन इल्लीगल है। यह भी लिखा गया है कि संविधान के अनुसार इसको रुपया देना ग़बन के ख़तरे से ख़ाली नहीं है। रुपये का कैसे ग़बन और गड़बड़ चलता है उसके बारे में मैं आपको बतलाऊं कि सोशल वेलफ़ेयर बोर्ड के चेयरमैन ने १ मार्च, १९६१ को पेमैंट आफ पे ऐंड एलाउन्सेज़ के लिए ५६३५ रुपये का सैल्फ़ चैक ईश्यु किया जोकि २६-६-६१ को इनकैश हुआ। एक और ५७०६ रुपये का सैल्फ़ चैक उनको १ अप्रैल, १९६१ को ईश्यु हुआ जोकि २६-६-६१ को इनकैश हो गया। कैशियर ने यह टोटल रुपया कैश बुक रजिस्टर में नहीं चढ़ाया और वह तमाम रुपया ग़बन हो गया। इसके ऊपर पुलिस का केस चला और कोर्ट का फैसला हुआ मगर पता नहीं कि आज तक उस सिलसिले में क्या हो रहा है?

इसके बाद मैं त्रिपुरा में कुछ इमारतें बनने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सन् १९५७-५८ में त्रिपुरा में कुछ इमारतें बननी थीं। दो केसों में जो स्कूल की इमारतें बननी थीं उसके लिए जितने रुपये की ग्रान्ट थी उससे १००००, १०००० रुपये अधिक खर्च हुए। ज्यादा रुपया जो इस तौर से खर्च हुआ उसका देखभाल करने के लिए कोई टेक्निकल स्टाफ़ उस के सुपरविज़न के लिये नहीं था। ६ केसेज़ में तो कोई फौरमल एग्रीमेंट भी कंट्रैक्टर से नहीं हुआ। कोई अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी भी ठेकेदार से नहीं जमा कराई गई। पी० डब्ल्यू० डी० की देखरेख में भी वे नहीं बनी। को ईमेज़रमेंट की किताब भी नहीं रखी गई। कोई कम्पलीशन सर्टिफिकेट भी क़ायदे से ईश्यू नहीं किया गया। बस इधर उधर से वैरीफिकेशन व सर्टिफिकेट इकट्ठा करके पेमेंट हो गया।

दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि उसने अपनी मनमानी से २०० रुपये से ४०० रुपये तक की कुछ जगहें सेंक्शन कर लीं जबकि मिनिस्टरी आफ एजुकेशन के सन् १९५० के आर्डर के अनुसार दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन केवल १२० से ३०० तक की ही जगहें क्रीएट कर सकता था । यह ग़लती सन् १९५७ में पकड़ी गई लेकिन सन् १९६० तक इसी स्केल से पेमेंट होता रहा । पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के बार बार कहने पर भी कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिएं, उसके बावजूद भी २० मास्टर और रख लिये गये ।

ऐक्सट्रा ऐक्सपेंडीचर और ऐक्स्ट्रा पेमेंट की एक बात मैं आपको और बतलाना चाहता हूं कि एक सैकेंड सैक्रेटरी वाशिंगटन डी० सी० इम्बैसी में मई, १९६० में नियुक्त हुए । उनका प्रमोशन फर्स्ट सैक्रेटरी में किया । उनको फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर वर्क करने की इजाज़त हो गई तो महाशय फर्स्ट सैक्रेटरी के एलाउंस ड्रा करने लगे । पहले सेक्रेटरी को इनक्रीज़ रेट एलाऊड नहीं था लेकिन वह बढ़ा हुआ भत्ता ड्रा करने लग गये । जब यह चीज़ मालूम हुई, आर्डर भी १४ जून को मिला मगर उसके बावजूद भी सेक्रेटरी साहब ने १६ जून को ३०० डालर महीने का घर दो साल के लिये ले लिया और लीज़ भी तय कर ली ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक, एक केस इस तरह से यहां पर नहीं ले सकते हैं जब तक कि उसके लिए उन्होंने एडवांस नोटिस मिनिस्टर साहब को न दिया हो ।

श्री विश्राम प्रसाद : यह तो मैं पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट से कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट में है ?

श्री विश्राम प्रसाद: जी हां, रिपोर्ट में है । १४ जून को उन्हें इसके लिए चिट्ठी भी मिल जाती है कि आप इस तरह नहीं कर सकते लेकिन इसके बावजूद १६ जून को उन्होंने ३०० डालर पर मंथ के हिसाब से दो साल के लिए एक मकान तय कर लिया । सरकार ने फरवरी, १९६१ में रैगुलराइज़ कर दिया । इस तरह से मिनिस्टरी को १०६६१ रुपये अधिक देने पड़े । बजाय इसके कि वह रुपया उनसे वसूल होता या और कोई ऐक्शन उनके खिलाफ़ लिया गया होता, वह रैगुलराइज़ कर दिया गया ।

मैं एक बात और आप से अर्ज़ करना चाहता हूं । मिनिस्टरी के एक अफ़सर ने १·२८ लाख रुपया २२-३-५२ और ३१-३-५२ के बीच कोआपरेटिव क्रैफ्ट स्कूलों के लिये निकाला । और यह रुपया करैंट एकाउन्ट में रक्खा गया । १·२८ लाख में से १·१३ लाख रुपये का पेमेंट जनवरी १९५५ तक अर्थात् तीन वर्ष में हुआ । अगर वह रुपया बजाय करैंट एकाउन्ट में रखने के गवर्नमेंट एकाउन्ट में रक्खा गया होता, अगर गवर्नमेंट के खज़ाने में रहता तो वह सूद वग़ैरह की शक्ल में बढ़ता रहता लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस रुपये पर ३ से ४ फ़ीसदी का सूद भी इन ८, १० सालों में मिलना था । इतना ही नहीं अब उसको कर्ज न समझ कर आउटराइट ग्रान्ट के रूप में ट्रीट किया जायेगा । इतना ही नहीं इन स्कूलों को २,३६,००० रुपया मिनिस्टरी आफ रिहैब्लिटेशन मिनिस्टरी ने भी दिया । उसके बाद फिर मिनिस्टरी आफ़ एजुकेशन ने इनको १,२७८,५०० दिया अब उसका कोई हिसाब नहीं वह क्यों दिया गया और उसका क्या मक़सद है । अब उसको लम्पसम ग्रांट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। १४५०० रुपया ३ मार्च, १९५९ को अर्थात् सात साल बाद गवर्नमेंट के खज़ाने में रिफंड हुआ । इन चीजों के ऊपर आडिट रिपोर्ट में कहा गया है और सरकार को इन पर अपना ध्यान देना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्राम प्रसाद]

आखिर में मैं केवल एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । सन् १९५१ के सैंशस के मुताबिक़ इस देश में २८ करोड़ और ३९ लाख के लगभग लोग अशिक्षित थे सन् १९६१ के सैंशस के अनुसार इनकी संख्या बढ़ कर ३३ करोड़ और ३९ लाख के लगभग हो गई है । मैं चाहूंगा कि देश में शिक्षा को बढ़ाने के लिए लिटरेसी को बढ़ाने के लिए अधिक तेज़ क़दम उठाये जायें ताकि यह देश शिक्षा की तरफ़ और अधिक तेज़ी से बढ़ सके ।

†**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** (कचार) : राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में राज्यों को ५० प्रतिशत सहायता द्वारा वृद्धि करने की जो योजना शुरू की है उसका स्वागत है । आशा है कि राज्य सरकारें इस योजना को उचित रीति से पूरा करेंगी ।

ऐसा प्रतीत होता है कि तृतीय योजना के अन्त तक लाखों स्कूल के बच्चों के लिए भोजन की योजना को बढ़ाया जाएगा, परन्तु ऐसा महसूस होता है कि कई बच्चे इस योजना में नहीं आ सकेंगे ।

शिक्षा के गुण प्रकार का सुधार करने के लिए अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है । अतः अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए अधिक संस्थाए खोली जाएं ।

सैकेंडरी क्रम पर विद्यार्थियों को चार भाषाएं सीखनी पड़ेंगी । १२ से १५ वर्ष के बच्चों के लिए चार भाषाओं का सीखना असम्भव है । यदि प्रादेशिक भाषाओ को विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो इस से राष्ट्रीय एकीकरण में रुकावट पड़ेगी । महिलाओं की शिक्षा के लिए तृतीय योजना में १ करोड़ रुपया अलग से निर्धारित कर दिया गया है । आशा है कि आपात के कारण महिलाओं के शिक्षण के लिए रखी गई राशि में कमी की जाएगी ।

आपातकाल में प्रविधिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । इसमें यह कठिनाई है कि देश में अपेक्षित प्रविधिक व्यक्तियों की कमी है । कचार में एक इंजीनियरी तथा एक मैडिकल कालिज खोला जाए ।

सरिसका, अलवर में राष्ट्रीय अनुशासन के केन्द्रों की तरह सभी राज्यों में केन्द्र खोलने चाहिएं ।

जब तक हिन्दी के विकास के प्रयत्नों को तीव्र नहीं किया जाता तब तक हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान नहीं ले सकती । संस्कृत के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम अच्छे बनाए जाएं ।

†**श्री मोहसिन** (धारवाड़ दक्षिण) : देश की प्रगति में शिक्षा का बहुत महत्त्व है । अतः हमें बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना है ।

यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । पहले में मुकाबले के शिक्षित लोग अधिक हैं । साक्षरता प्रतिशत भी अधिक है । हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं । स्कूलों में पढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं ।

स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, परन्तु शिक्षा का स्तर गिर रहा है । विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है । इस सम्बन्ध में सुधार किया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्याह्न योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें अधिक धन नहीं दे सकतीं क्योंकि जनता अपना अंशदान नहीं देती है। सरकार सुनिश्चित को सुचितर करना चाहिए कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए पृथक रक्षित निधियों का प्रयोग करें उन निधियों को अन्य प्रयोजनों के लिए काम में न लाया जाए ।

कई लोग इतने गरीब हैं कि वे बच्चों को पाठ्य पुस्तकें भी नहीं खरीद कर दे सकते अतः कम से कम प्राइमरी क्रम पर पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाएं ।

वर्तमान इतिहास की पुस्तकों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि देश की एकता के लिए हानिकारक हैं और इससे नवयुवकों के दिल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतः हमारी इतिहास की पुस्तकों के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पुनः लिखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि इतिहास की वर्तमान पाठ्य पुस्तकें देश में राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं ।

लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे अच्छी माताएं बन सकें । स्त्रियों का क्षेत्र घर है । घर के उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निभा सकने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए ।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम निर्धारित करने में भाषाई अल्प-संख्यकों के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए । प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विश्वविद्यालय होने चाहिएं ।

प्रत्येक योग्य छात्र को ऋण-छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए । सरकार को इस बारे में प्रबन्ध करना चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जो अच्छा काम किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहती हूं । अभी अभी हमारी बहन कह रही थीं कि इसके लिये टाइम कम दिया जाता है । मैं कहना चाहती हूं कि इसके लिए टाइम ही कम नहीं दिया जाता है बल्कि पैसा भी कम दिया जाता है फाइनेन्स वाले या प्लानिंग वाले, जो जबर्दस्त होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, उनको तो पैसा ज्यादा दे देते हैं लेकिन जो कमजोर होते हैं जो बगावत नहीं करते हैं, उनको पैसे कम देते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसी है जो बगावत नहीं कर सकती है, उसमें नम्रता अधिक है । और बजट में जो इसके लिये फंड्स थे, उनको घटा कर १ करोड़ ६९ लाख रुपया कर दिया गया है । मैं मानती हूं कि देश पर संकट है और हमारा देश संकट में से गुजर रहा है और इस संकट का मुकाबला करने के लिये हमें पैसे की आवश्यकता है । हम सब मिनिस्ट्रीज़ के बजटों को बढ़ा रहे हैं और हम ने केवल मात्र एजुकेशन को ही इतना कम इम्पॉर्टेंट समझ लिया है, कि इसके हम पैसे कम कर सकते हैं ।

अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि परसेंट जो लिट्रेसी का है, वह कम है, एफिशेंसी कम हो गई है और बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, उनमें बगावत करने की भावना घर कर रही है । ये सब बातें सही हैं । लेकिन मैं तो समझती हूं "सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ते" । पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता है । एक तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को कम पैसा मिला है और सरकार की नजर सिर्फ इसी मिनिस्ट्री पर ही पड़ी है, लेकिन मैं देखती हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की नजर भी केवल गर्ल्ज़ एजुकेशन पर पड़ी है और उस पर जो खर्च किया जाता था, उसको कम कर दिया गया है । सब की नज़र एजुकेशन मिनिस्ट्री पर पड़ती है और एजुकेशन मिनिस्ट्री की नजर गर्ल्ज़ एजुकेशन पर कम जाती है । मुझे खुशी है कि एक प्रामिज़

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

हमारे साथ किया गया था। लेकिन मुझे दुःख है कि उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पिछले साल नेशनल काउंसिल फार एजुकेशन आफ़ विमन वाले प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए थे और उनसे प्रार्थना की थी कि जो ग्यारह करोड़ इस काम के लिये रखा गया है इसको बढ़ा कर सतरह करोड़ कर दिया जाय। उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था। पिछले साल जब इस मिनिस्ट्री की डिमांड्ज़ पर बहस हो रही थी तो उसका जबाब देते हुए मिनिस्टर साहब ने भी इसके बारे में वादा किया था और कहा था कि इसको जरूर करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अब भगवान की मार देखिये कि ११ करोड़ को भी घटा कर साढ़े दस करोड़ कर दिया गया है, यानी पचास लाख कम कर दिया गया है। मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहती हूं कि कुछ दिनों से हमारे मिनिस्टर साहब ने सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स चलाई हैं। लेकिन जो हमारी स्टेट्स हैं वह गर्ल्स एजुकेशन के वास्ते दिल खोल कर काम नहीं करती हैं। और कुछ तगड़ी स्टेट्स इसके लिए कोई स्कीम भेजती हैं तो यहां पर उन की ताईद नहीं होती है। आप को इसके लिये जरा ताकत से काम करना चाहिये। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन को आप करोड़ों रुपये देते हैं लेकिन वहां पर गर्ल्स एजुकेशन के वास्ते कोई रिस्पांस नहीं है। आप के दिल में गर्ल्स एजुकेशन के लिये श्रद्धा है, आज गर्ल्स एजुकेशन ज्यादा बढ़ रही है इसलिए उनकी एजुकेशन के लिये स्कीम्स लाने की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि हमारे लिए गर्ल्स एजुकेशन कितनी इम्पार्टेंट है। दूसरे मुल्कों वाले अपनी औरतों को बहुत ताकतवर समझते हैं। हजारों औरतें यहां आकर अपने स्कूल्स बनाती हैं, लोगों के दिलों को कन्वर्ट करती हैं, औरतों को ट्रेन करती हैं और यहां पर चालीस या पचास साल काम करने के पश्चात् अपने देश वापिस चली जाती हैं। मैंने पहले भी सवाल पूछना चाहा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ देखते भी नहीं, न कभी समय देते हैं। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि चाइना वालों ने कोशिश करके, प्लेन कर के हमारे बार्डर पर दस हजार औरतें भेज दीं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में जाना है और वहां बसना है, यहां के लोगों को कन्वर्ट करना है, शादी करना है और बच्चे पैदा करना है। वह लोग इस तरह से काम करते हैं। लेकिन हमारे यहां औरतों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। पुराने जमाने में हमारे यहां की औरतें कोई भी युनिवर्सिटी नहीं जाया करती थीं, कोई भी डिगरी नहीं लिया करती थीं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बड़ी ऊंची शिक्षा दिया करती थीं। अभी हम लोग राजेन्द्र बाबू ऐसे आदमी के लिए अफसोस कर रहे थे कि वे चले गये, जब गांधी जी मरे थे तब भी पंडित जी के मुंह से वह शब्द निकले थे :

"हमारे जीवनों से रोशनी चली गयी है। हर स्थान में अन्धेरा है"

ऐसी ज्योति देने वाले जो लोग होते है उन को ऐसा बनाने वाला आखिर कौन है? उनकी मायें उनको सिखाया करती हैं। गांधी जी को उन की मां ने सिखाया था कि भगवान की पजा करो, सबेरे उठ कर नहाओ। उसी प्रकार से वे खाने के पहले पूजा किया करते थे, उसके बाद भोजन करते थे। कथा, कालक्षेप, रामायण, पुराण, भागवत सब कुछ पढ़ा करते थे। कारण यही है कि मायें अपने बच्जों को देव शक्ति से बांध कर रखती थीं इन नियमों से। आप लाख यूनिवर्सिटी या कालेज खोल दें लेकिन काबू में रखने वाली मांयें ही होती हैं। मैंने बचपन में देखा कि यहां पर साइमन कमिशन आया था, उस समय यहां के लोगों ने बगावतें की थीं लेकिन वह केवल राजनीति में थीं। बच्चों में आजकल बगावत की सी भावना नहीं होती थी। उन की कल्चरल ट्रेनिंग होती थी, वे प्रिंसिपल आफ एथिक्स पढ़ते थे। उस समय की औरतें स्कूलों और कालेजों में पढ़ने नहीं जाती थीं लेकिन उनको सब कुछ कंठस्थ होता था जो कि बच्चों को बतलाती थीं, उन को भजन सुनाती थीं और अच्छी अच्छी आदतें उन की डालती थीं। अभी मैंने सुना कि लखनऊ के लड़कों ने जाकर रेल में दंगा किया। इसका कारण यह है कि आजकल के स्कूलों में अच्छा वातावरण

नहीं, एजुकेशन के अन्दर एथिक्स का कोई स्थान नहीं है। आज कल की शिक्षा बच्चों को नास्तिक बना रही है, उन को भगवान के अस्तित्व का पता नहीं है। उन कों ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न तो सोसाइटी में, न घर में और न स्कूल में। इसीलिये आज कल इन्डिसिप्लिन ज्यादा हो रही है। इसलिये आज सोसाइटी को बदलने की जरूरत है। इसके लिये गर्ल्स की एजूकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मोहसन साहब ने यही तो शिकायत की थी अभी। वह यह कह रहे थे कि माताये पार्लियामेंट में आ जाती हैं और बच्चे पीछे रह जाते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : मैं तो खुद ही कह रही हूं कि आप औरतों को अच्छा बनाने के लिये काफी पैसा नहीं देते। वैसे मैं १०० बच्चों को सम्भाल रही हूं। मैं आप से कहना चाहती हूं कि :

"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता"

जहां पर औरतों की पूजा होती है, मान होता है, उन को गौरव दिया जाना है वहां देवता भी खुश होते हैं। जहां पर यह नहीं होता वहां पर कुछ नहीं होता। मैं आप से कहना चाहती हूं कि यदि औरतों की तरफ ध्यान दिया जाये तो औरतें एफिशिऐंसी में किसी से कम नहीं हैं। आज वह इन्स्टिट्यूशन्स चलाती हैं, महकमों में काम करती हैं, रेलवे स्टेशन पर काम करती हैं, इस प्रकार जहां कहीं भी काम करती हैं पूर्ण सफल रहती हैं। फिर भी आप बजट में रुपया ले कर भी औरतों की एजूकेशन को इम्पोर्टें नहीं देते।

जब तीसरी योजना बनी थी तब उस में एजूकेशन के लिये ९८० करोड़ रू० रक्खे गये थे, लेकिन घटते घटते वह ३७० करोड़ रु० रह गये। उस में भी गर्ल्स एजूकेशन के लिये बहुत कम रुपया रखा गया है। वाजिब प्रपोर्शन तो उन के लिए रखना चाहिये था। उन के आधे से ज्यादा वोट्स होते हैं, ५२ पर सेंट यहां की पापुलेशन उन की होती है लेकिन यहां पर उन को एक तिहाई या चौथाई भी हिस्सा नहीं दिया जाता। उन को मुश्किल से ८ या १० परसेंट दिया जाता है। इसी वजह से आज बच्चों की और लड़कियों की खराबी हो रही है। उन पर पूरी तौर पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। आज एजूकेशन के सिलसिले में सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स चलती हैं उन के लिये आप ने ११ करोड़ रु० रखा है। लेकिन उस म से भी पूरा रुपया खर्च नहीं हो रहा है।

हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर सौभाग्य से यहां बैठे हुए हैं। मैं उन से कहन चाहती हूं कि लास्ट इअर एजकेशन के बजट पर २१ करोड़ रु० रखा गया था। उस में अब की १ करोड़ ६९ लाख रु०की कमी कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप का समय अब पूरा हो गया।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से कहना चाहती हूं कि आप को जो भी पैसे की कमी पड़ती है वह आप और मदों में से कमी करके पूरा कर लें। आप एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च में से पूरा करलें लेकिन एजूकेशन से, खास तौर से गर्ल्स एजूकेशन में से नहीं लिया जाना चाहिये।

इस के बाद मैं संस्कृत और हिन्दी के अध्यापकों के बारे में कहना चाहती हूं। आप उनको आगे लाने के लिये कुछ और कोशिश करें। इडिपेंडेंस के पहले तो उन की हालत खराब थी ही लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि उन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी यह सोचते हैं कि पढ़ने के बादवह क्या करेंगे। इस लिये लोग संस्कृत से दूर ही रहते हैं। मैं कहन चाहती हूं कि जब तक उन को आप ईक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते, सब के बराबर तन्ख्वाह नहीं देते, उस वक्त तक कुछ होने वालानहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप का समय समाप्त हो चुका है आब आप खत्म कीजिये ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : आप बजट में तो पैसा कम कर ही देते हैं,यहां बोलने तो दीजिये । जो विषय ऐसे हैं जिन पर अधिक भाषणों की आवश्यकता नहीं है, उन के लिये आप ज्यादा समय देते हैं, पांच पांच घंटे देते हैं लेकिन एजूकेशन के लिये चार घंटे देते हैं क्योंकि आप उस को बहुत इम्पार्टेंट नहीं समझते ।

आप के जो कन्डेन्स्ड कोर्सेज़ चल रहे हैं वे बहुत अच्छे चल रहे हैं और मैं मंत्री महोदय को इस के लिये बधाई देती हूं । लेकिन उन की पूरी रिपोर्टस नहीं आ रही है । सन् १९६०–६१ की रिपोर्टस आई हैं । इस मामले में बिहार भी पीछे है और उड़ीसा भी पीछे है । वह आगे नहीं आ रहे हैं । इस की तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये ।

हमारे कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं जैसे कि यूथ फैस्टिवल्स हैं, यूथ होस्टल हैं । इनको बन्द कर दिया जाय । मैंने आप के बजट को देख लिया है । मैं इन चीजों में कमी कर के गांधियन लिटरेचर के प्रचार के लिये पैसा दिया जाय क्योंकि इस मद में बहुत कम पैसा रखा गया है । इस के लिये सिर्फ ७९,००० रु० रखे गये हैं । इस के अनुसार कई ऐसी चीजें हैं जो कि औरतों की बाबत हैं । मैं चार साल से मुसलसल चिल्ला रही हूं कि हमारी औरतें १ बजे से ३ बजे तक घर में खाली रहती हैं । उन गृहणियों का उस समय में कुछ सिखलाने के लिये अलग से प्रबन्ध होना चाहिये । गांधियन प्रिंसिपल पर सारा काम होना चाहिये । यह जो लिटरेचर है उस के लिये बड़े अच्छे लोगों को सब जगह पर भेज कर प्रचार करवाइये । जब साइमन कमिशन भारत में आया था उस वक्त मैं स्टूडेंट थी । उसके खिलाफ प्रचार करने के लिये बड़े बड़े नेता आते थे । यही चीज इस समय भी होनी चाहिये ।

बहनों के लिये मिड डे स्कूल्स आप को चलाने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : बच्चों को यह तो सिखाया नहीं गया है कि वे घंटी की भी परवाह न करें । श्री बैरो ।

†**श्री बैरो** (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : इस सभा पर काफी उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमें थोड़े से घण्टों में कई करोड़ रुपये मंजूर करने पड़ते हैं । एक प्रक्रिया ऐसी बनाई जाये जिस से सारी सभा को विभिन्न समितियों में बांट दिया जाये जिस से मंत्रालयों की मांगों पर अधिक विस्तार से बातचीत हो सके ।

आपातकाल में शिक्षा और इस के क्रियात्मक ढंग से कार्यान्वियन में राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए । सारे देश के लिए एक ही शिक्षा नीति बनाने के बारे में भावुक एकीकरण समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये । उस सिफारिश पर मंत्रीमण्डल द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए । केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय बोर्ड द्वारा निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां राजनीति घुस गई है ।

सारे देश में माध्यमिक शिक्षा के तरीके भिन्न हैं । कहीं हायर सेकेन्डरी है और कहीं इंटर-मीडियेट । माध्यमिक शिक्षा का तरीका देश भर में समान रूप से बनाया जाना चाहिए । माध्यमिक शिक्षा के कई मिश्रित तरीकों से कई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और उन में से एक यह है कि स्कूलों के विद्यार्थियों को जहां वाह्य परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, सरकारी नियुक्तियों के बारे में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा हानि होती है । रेजीडेंटल स्कूलों के विद्यार्थियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, विशेषकर अब जो सेना में कमिशन दिये जा रहे हैं उन में जाने के लिए ऐसे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आपातकाल में मंत्रालय ने स्कूलों को जो छोटी छोटी पुस्तकें भेजी हैं वह बहुत अच्छी हैं उस के लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है।

शारीरिक शिक्षा योजना और राष्ट्रीय अनुशासन योजना को मिलाना चाहिए । योजना का नाम भी बदल कर शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय अनुशासन के लिए आपात योजना रखना चाहिए। ये योजनायें एक ही निदेशालय के अधीन होनी चाहिएं ।

पब्लिक स्कूलों में राष्ट्रीय सेना छात्र दलों के कार्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता है । विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के उद्देश्यों की जांच की जाये । यदि यह सशस्त्र बलों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति है, तो यह योजना सब के लिए अनिवार्य बनायी जाये ।

विज्ञान गुण योजना लाभदायक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत प्रयोग की गई भाषा अंग्रेज़ी होनी चाहिए । देश में विज्ञान की प्रगति के लिये इस भाषा का प्रयोग अच्छा रहेगा । इस सम्बन्ध में मुझे प्रधान मंत्री का भी समर्थन प्राप्त है ।

श्री रणंजय सिंह (मुसाफ़िरखाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे शिक्षा मंत्रालय की बजट मांगों पर अपने विचार प्रकट करने का मौक़ा दिया । मैं अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा शिक्षा मंत्रालय को बधाई दूंगा कि उसने बहुत से ऐसे कार्य किये हैं जिनकी कि प्रशंसा की जा सकती है ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं थोड़ा ही निवेदन करूंगा । अब शिक्षा का अभिप्राय: तो यह है कि लोग शिक्षित होकर अच्छी से अच्छी बातें सीखें और देश के लिए वह लाभदायक सिद्ध हों, देश के वह उपयोगी नागरिक बनें । लेकिन खेद का विषय है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अभी उसी पुरानी लार्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली के ढंग पर ही बहुत कुछ चल रही है, कुछ संशोधन अवश्य हुआ है लेकिन अभी तक प्राय: उसी प्रकार से चली आ रही है । लार्ड मकाले का यह उद्देश्य था कि भारतवासी अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करें लेकिन साथ ही साथ उनके विचार ऐसे बदल दिये जांय कि वे रंग में तो भले ही भारतीय रहें परन्तु और सब चीजों में विदेशी हो जांय । इस के साथ ही उनका यह भी उद्देश्य था कि भारतवासी अंग्रेज़ सरकार की दासता को भी स्वीकार किये रहें । उन में स्वाधीनता की भावना उत्पन्न न होने पाये । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज की शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । सब से पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लार्ड मैकाले को उत्तर दिया । उन्होंने केवल यही नहीं कहा कि वह शिक्षा-प्रणाली इस देश के लिए अनावश्यक और अनुपयुक्त है और इसलिए उस के स्थान पर कोई दूसरी शिक्षा-प्रणाली हो, अपितु उन्होंने एक ऐसी पठन-पाठन प्रणाली के प्रचार तथा प्रसार का सुझाव दिया और उस के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की, जो न केवल हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार है, अपितु वर्तमान समय में भी इस देश के लिए लाभदायक और अनुकूल है ।

आज हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी गड़बड़ी जान पड़ती है, कहीं कहीं पर हमारे विद्यालयों में स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता एवं उच्छृंखलता का जो प्रदर्शन होता है, वह सब क्यों हो रहा है और अनुशासन की रक्षा क्यों नहीं हो रही है ? मैं समझता हूं कि इस के कई कारण हैं ।

शिक्षा के क्षेत्र में जहां अन्य अनेक सुधारों की आवश्यकता है, वहां मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सहशिक्षा की प्रणाली उचित नहीं है । वह न केवल हमारे देश के, अपितु कहीं के भी अनुकूल नहीं है । उस के कारण बहुत सी अवांछनीय बातें पैदा हो रही हैं । इसलिए हम को इस विषय

[श्री रणंजय सिंह]

गम्भीरता से विचार कर के उचित सुधार करने का प्रयास करना चाहिए । सहशिक्षा के रे में स्वामी दयानन्द ने बताया है—कुछ अपने मन से नहीं, अपितु प्राचीन शास्त्र और इस देश परम्परा और संस्कृति के अनुसार उन्होंने यह विचार प्रकट किया है—कि कन्या-पाठशालायें अथवा कन्याओं के गुरुकुल और लड़कों के गुरुकुल कम से कम दो दो कोस अथवा चार चार मील की दूसरी पर रहने चाहिएं और बालकों को बचपन से ही ब्रह्मचर्य के साथ सदाचार की शिक्षा दी जाये, ताकि वे अपने चरित्र का निर्माण करें और बड़े हो कर आदर्श नागरिक बनें । इस प्रकार से जब उन का चरित्र उत्तम होगा, तो उन में अनुशासन भी होगा और उन में सभी प्रकार के गुणों का समावेश होगा और विद्यार्थीगण आज कहीं कहीं पर जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, जिन से दुःख होता है, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी ।

इस के साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राचीन पठन-पाठन-प्रणाली का नाम लेने से यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों को वर्तमान समय की शिक्षा न दी जाये, उन्हें आज-कल की आवश्यक बातें न बताई जायें, उन बातों से उन को अनभिज्ञ रखा जाये । यह अभिप्राय नहीं है । मेरा तात्पर्य यह है कि उन को वर्तमान समय के अनुकूल उचित और पूर्ण शिक्षा दी जाये और उन को आधुनिक समय के उद्योग आदि भी सिखाये जायें । लार्ड मैकाले की शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य यह था कि छात्र केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ें और विद्या-उपार्जन एवं ज्ञान प्राप्त करना उन का लक्ष्य न हो । अगर प्राचीन पठन-पाठन-प्रणाली का प्रचार होगा और उस के साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान भी उपलब्ध कराया जायेगा, तो वे समझेंगे कि जहां वे विद्या, ज्ञान और बल प्राप्त कर रहे हैं, वहां वे धन भी प्राप्त करेंगे ।

हमारे यहां विद्या का यह उद्देश्य बताया गया है :

विद्या ददाति विनयं
विनयाद्याति पात्रताम् ।
ा त्रत्वाद्धनमाप्नोति
धनाद्धर्मः ततः सुखम् ।।

विद्या हम में विनय और नम्रता का भाव उत्पन्न करती है, लेकिन आज उस का सर्वथा अभाव दिखलाई देता है, क्योंकि विद्या इस उद्देश्य से नहीं दी जा रही है । प्रायः—सब जगह नहीं, प्रायः—लोग केवल मात्र धन को प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पढ़ते हैं । विद्या हमें विनय देगी और उस के पश्चात् हम में योग्यता और पात्रता आयेगी । जब हम में योग्यता होगी, तब हम धन भी प्राप्त करेंगे और जब धन होगा, तो हम धर्म का पालन करेंगे और अगर धर्म होगा, तो हमें सुख भी प्राप्त होगा । हमारे यहां विद्या के ये उद्देश्य बताये गये हैं । अगर हम इन उद्देश्यों को ले कर चलें, तो हमारे देश का बहुत कल्याण हो सकता है ।

स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज ने, जो कि लार्ड मैकाले के पश्चात् आदि गुरुकुल प्रणाली के संस्थापक थे, आज से साठ वर्ष पूर्व छपी हुई अपनी पुस्तक में लिखा था कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली भ्रष्टाचार का प्रसार करेगी, क्योंकि इस में खर्च, व्यय इतना अधिक है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना पसा नहीं पा सकेंगे । अगर कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे को पढ़ायेगा, तो अपने दूसरे बच्चों, पौत्रों आदि, को पढ़ाने के लिए उस को पैसा नहीं मिलेगा । उस के सामने दो ही मार्ग होंगे—या तो वह उन को न पढ़ाये, अथवा वह किसी न किसी प्रकार से धन प्राप्त करे । इसलिए पता नहीं कि पैसा पाने के लिए वह किन किन उपायों का अवलम्बन करे । मैं निवेदन

करना चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली बहुत महंगी है और इस में इस प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाये कि इस पर व्यय कम हो और इस से लाभ अधिक हो ।

जहां तक सदाचार का सम्बन्ध है, मेरी प्रार्थना है कि इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाये कि किसी भी विद्यालय के क्षेत्र में, चाहे वह अंग्रेज़ी भाषा का हो और चाहे और किसी भाषा का, नशे के सेवन का पूर्णतया बहिष्कार रहे । वहां पर कोई धूम्रपान भी न करने पाये । इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न होने का परिणाम यह है कि विद्यार्थी बचपन में ही धूम्रपान और अन्य नशों में पड़ जाते हैं । इस के साथ ही अश्लील और शृंगार-विषयक चित्रों का विद्यालयों में प्रवेश न होने दिया जाये । जहां तक हो सके, बाहर सड़कों पर भी ऐसे चित्रों को अगर न लगाने दिया जाये, तो इस से भी लाभ होगा, क्योंकि आम लोगों और विशेषतया विद्यार्थियों पर ये चित्र कोई अच्छे भाव पैदा नहीं करते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया शिक्षा का प्रसार किया जाये । इस से देहात के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी और साथ ही व्यय भी कम होगा । इस प्रकार पढ़-लिख कर वे अपने घरों में ही काम कर सकेंगे और उन का उद्देश्य यह नहीं होगा कि पढ़-लिख कर वे कहीं नौकरी करने जायें ।

चूंकि अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़े शब्दों में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं इस क्षेत्र में बाल्यावस्था से ही कार्य कर रहा हूं । इसलिए अपने विचार रखने के लिए मुझे अधिक समय चाहिए था । यदि मैं उधर होता, तो शायद मुझे अधिक समय मिलता, लेकिन चुंकि काफ़ी माननीय सदस्यों ने बोलना है, इसलिए मैं जल्दी समाप्त कर देता हूं ।

श्री यशपालसिंह (कैराना) : इधर आने के लिए निमंत्रण है । माननीय सदस्य इधर आ जायें ।

श्री रणंजय सिंह : मैं केवल समय के बारे में कह रहा हूं ।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यालयों में देशी व्यायाम पर अधिक ध्यान दिया जाये ।

पहले गुरुकुलों के लिए छः लाख रुपया रखा गया था । उस के लिए बहुत धन्यवाद । लेकिन अब उस में कमी कर के तीन लाख कर दिया गया है । मंत्री महोदय को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसी योजना बनायें कि विद्यार्थियों को वास्तविक लाभ हो और उच्छृंखलता दूर हो और हमारे देश के बालक वीर, योग्य, बलवान और धनवान बनें, जिस से बड़े हो कर वे राष्ट्र की सेवा कर सकें और हमारे देश की अच्छी अच्छी योजनाओं को सफल करने में सहायक हो सकें ।

इन शब्दों के साथ में मैं श्रीमान् जी को धन्यवाद देता हूं और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** (छतरपुर) : शिक्षा मंत्रालय ने प्रारम्भिक, सैकेन्डरी और कालिज शिक्षा में काफी अच्छा काम किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० त्रि० शर्मा]

आपातकाल के कारण शिक्षा के लिये आवंटन में कमी नहीं की जानी चाहिये।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार करने की चेष्टा करनी चाहिये। सभी विश्वविद्यालयों में तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का ठीक प्रकार से कार्यान्वियन किया जाना चाहिए।

सरकार को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम को अन्तिम रूप देना चाहिए यद्यपि कुछ प्रोफेसर शिक्षा माध्यम में परिवर्तन के विरुद्ध हैं कम से कम उन क्षेत्रों में जहां प्रवज भाषा हिन्दी है शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। हमें हिन्दी को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहियें। इस के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से कहा जा सकता है तथा प्रकाशक भी इस कार्य को हाथ में लेने को तैयार हैं।

कालेज स्तर की पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन करना अनिवार्य है। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करे।

भारतीय इतिहास में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इतिहास को वास्तविक तथ्यों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। जिन तथ्यों का इतिहास में गलत निरूपण किया गया है उन्हें हटा दिया जाये मैं शिक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं।

संस्कृत के प्रचार तथा संस्कृत पंडितों की ओर शिक्षा मंत्री काफी दिलचस्पी ले रहे हैं तथापि इस सम्बन्ध में काफी प्रचार करने की आवश्यकता है क्योंकि गांवों में रहने वाले पंडितों को इस सम्बन्ध में जानकारी ही नहीं हो पाती। संस्कृत संस्थाओं में पढ़ाने वाले पंडितों को हाई स्कूल की आरम्भिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले पंडितों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है। यह वैषम्य दूर किया जाना चाहिए।

जिन राज्यों में केवल एक विश्वविद्यालय है वहां एक अन्य विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाये।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : शिक्षा का विषय राज्य, केन्द्र तथा समवर्ती तीनों ही सूचियों में आता है। मेरे विचार से शिक्षा के क्षेत्र में विषमता को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा को समवर्ती सूची के अन्तर्गत ले आना चाहिये। उदाहरणार्थ गुजरात में तीन विश्वविद्यालय हैं जिन में एक में शिक्षा का माध्यम गुजराती, दूसरे में हिन्दी और तीसरे में अंग्रेज़ी है।

इस सम्बन्ध में संविधान में आवश्यक संशोधन किये जायें जिस से कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा समवर्ती सूची में आये इस प्रकार केन्द्र तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उन पर अधिक प्रभाव हो।

मेरा सुझाव है कि बालक की आरम्भिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में ही होनी चाहिए। मेरे विचार से अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दे कर युवक के चरित्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है।

शास्त्री भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस से कोई भी व्यक्ति प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं हूं कि मैं हिन्दी की मधुरता का कायल हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और वे इस प्रकार हैं ।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये भी स्कूलों के अध्यापकों की तरह प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायें ।

संविधान में संशोधन कर विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाई जाये ।

लेक्चर के घंटे कम कर के विद्यार्थियों को स्वयं पठन-पाठन के लिये प्रोत्साहित किया जाये तथापि पीरियड का समय बढ़ा दिया जाये जिस से अध्यापक अपना लेक्चर भली भांति दे सकें ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: मैं उन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मंत्रालय के कार्य की प्रशंसा की है । वस्तुतः शिक्षा की समस्यायें बहुत कठिन हैं तथा हमारे संसाधन उसे देखते हुए बहुत सीमित हैं ।

जहां तक आरम्भिक शिक्षा का प्रश्न है हम संविधान का निदेश पूरा करने में समर्थ नहीं रहे हैं । तथापि हम तीसरी योजना में इस के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । तथा योजना के प्रथम दो वर्षों में हम लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये हैं । आपात काल के कारण कुछ राज्यों को वित्तीय कठिनाई पैदा हो गई है और शायद वे शिक्षा सम्बन्धी मांगें पूरी न कर सकें । तथापि हम ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि इस गति को धीमा न किया जाये तथा तीसरी परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाये । हमें आशा है कि आपातकाल तथा कठिनाइयों के बावजूद हम तीसरी योजना में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होंगे क्योंकि राज्यों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि शिक्षा के द्वारा प्रतिरक्षा की क्षमता में भी वृद्धि होगी ।

हम नारी शिक्षा के सम्बन्ध में भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । हमने यह कहा है कि महिला संस्थाओं को शतप्रतिशत सरकारी सहायता मिल सकती है । हमने यह बता दिया है कि नारी शिक्षा के लिये धन केवल उसी कार्य में व्यय किया जायेगा वह धन किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जा सकता है ।

हम बच्चों को दुपहर के भोजन देने के सम्बन्ध में भी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । तीसरी परियोजना की अवधि में लगभग १ करोड़ बच्चे इस के अधीन आयेंगे । हम बच्चों को मुफ्त पुस्तकें इत्यादि दे कर उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं । तीसरी परियोजना में हम काफी जरूरतमंद को पुस्तकें देने में समर्थ होंगे ।

माध्यमिक स्तर में भी हम शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं । जहां तक शिक्षा के स्तर में गिरावट का प्रश्न है इस की जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक जांच समिति नियुक्त की है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रतिरक्षा की तात्कालिक समस्याओं तथा औद्योगिक विकास के लिये हमें बहुत से वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी । विज्ञान की प्रगति में अन्य देशों के समकक्ष आने में हमें काफी प्रयत्न करना होगा । हम माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के प्रचार का प्रयास कर रहे हैं। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के प्रचार के लिये हमें यूनेस्को तथा रूस से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

हम केन्द्र में विज्ञान की शिक्षा के विकास का विभाग खोल रहे हैं। यह विकास विज्ञान, गणित तथा उन की शिक्षा के सम्बन्ध में जांच करेगा। हम ऐसा वर्कशाप स्थापित कर रहे हैं जो बड़े पैमानों पर प्रयोगशालाओं का सामान बनायेगी। प्रयोगशालाओं में केवल स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा इस सम्बन्ध में हमें रूस के विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त हो रही है।

देश में चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना की गई है। ये विज्ञान, टेकनीकल तथा व्यावसायिक विषयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे। इन प्रशिक्षण कालेजों में चार वर्ष का प्रशिक्षण होगा। उन में उन्हें वैज्ञानिक तथा टेकनीकल विषयों के अध्यापन की शिक्षा दी जायेगी। आगामी ग्रीष्म ऋतु से विश्वविद्यालयों के सहयोग से विज्ञान के अध्यापकों के लिए कई ग्रीष्म पाठ्यक्रमों का आरम्भ किया जायेगा। इस कार्य में दिल्ली, पंजाब, पूना और मद्रास के विश्वविद्यालय सहयोग कर रहे हैं। आगामी वर्षों में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ये ग्रीष्म संस्थायें विश्वविद्यालय शिक्षा का अभिन्न अंग बन जायें। समय आने पर और अधिक संस्थायें खोली जायेंगी।

पिछले वर्ष मैंने यह बताया था कि हम स्नातकोत्तर कक्षाओं में उच्च स्तरीय गवेषणाओं को आरम्भ करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में चार केन्द्रों की स्थापना कर ली गयी है। तीसरी योजना के दौरान इस प्रकार के २० से ३० केन्द्रों की स्थापना कर ली जायेगी। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य ऊंचे स्तर म गवेषणा करना तथा विद्वानों के विभिन्न विषयों में अग्रेतर गवेषण सम्बन्धों सुविधायें देना है।

आगामी वर्ष हम पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। कई सदस्यों ने पाठ्य पुस्तकों के निचले स्तर की अलोचना की है। निसंदेह पिछले वर्ष दिल्ली में जिन किताबों का प्रकाशन किया गया वे घटिया दर्जे की थीं। मंत्रालय ने इस संबंध में जांच की थी। मुझे दुःख है कि बाजार में अभी भी ये किताबें बिक रही हैं और विद्यार्थी इनका उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा गवेषणा परिषद् ने अच्छे स्तर की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की एक व्यापक योजना बनायी है। हमने शिक्षा संबंधी साहित्य का निर्माण करने के लिये विशेषज्ञों की एक तालिका नियुक्त की है, वे भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास हिन्दी वस्तुतः सभी विषयों में पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे। इन पुस्तको के मसविदे एक वर्ष के भीतर तैयार हो जायेंगे। इसे सभी शिक्षा संस्थाओं, प्रकाशकों, लेखकों तथा संबंधित व्यक्तियों को उनकी राय जानने के लिये परिचालित किया जायेगा। उनके सुझावों को समाविष्ट करने के पश्चात् यह पुस्तक अंतिम रूप से प्रकाशित की जायेगी। इसका उद्देश्य इस मामले में प्रकाशकों या राज्य सरकारों से प्रतिद्वंदिता करना नहीं है। हमारा उद्देश्य अच्छे स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन करना है। ये पुस्तकें अगले वर्ष तक बाजार में आ जायेंगी। श्री मुकर्जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम अपनी भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर रहे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां तक वैज्ञानिक और प्रविधिक साहित्य का सम्बन्ध है, मंत्रालय अब लगभग सब प्रकार की पाढ़य पुस्तकें, प्रामाणिक पुस्तकें, निर्देश पुस्तकें, शब्द-कोष, लोक प्रिय पुस्तकें और बच्चों के हित की पुस्तकें प्रकाशित करने में लगा हुआ है। मैं सदन को यह भी बतलाना चाहूंगा कि हम ने पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने वाला कार्यालय स्थापित किया है, जो वैज्ञानिक और प्रविधिक शब्दावली आयोग के साथ काम कर रहा है। यह आयोग उस कार्यालय की सहायता से अब प्रामाणिक और लोक प्रिय पुस्तकें तैयार करने

और अनुवाद करने में लगा हुआ है। हम अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक ५० पुस्तकें तैयार करेंगे,। इस के अतिरिक्त बहुत सी मौलिक पुस्तकें अपनी भाषाओं में प्रकाशित की जायेंगी। निर्देश साहित्य में, मैं आशा करता हूं कि काफ़ी पुस्तकें उपलब्ध होंगी और इस के साथ ही भौतिक विज्ञान, रसायन गणित, वनस्पति विज्ञान और कृषि के सम्बन्ध में शब्द-कोष अवर-स्नातक अवस्था तक लगभग तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम एक एकीकृत शब्दावलि का हिन्दी-अंग्रेज़ी संस्करण भी तैयार कर रहे हैं। हम ने १११ पुस्तकों का प्रतिलिप्यधिकार भी ले लिया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुवाद कार्य हो रहा है। हमने आगामी वित्तीय वर्ष में पांच विभाग स्थापित करने का निश्चय किया है, जिस में योग्य प्राध्यापकों द्वारा मौलिक कार्य तथा अनुवाद कार्य किया जायेगा। यह सुझाव डा० गोविन्द दास का था। हमने बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों को लिख दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भी तीन और विभाग स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, हम साधारण पढ़ने वालों के लिए भी पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने ११५ पुस्तकों के लिए प्रकाशकों से प्रार्थना की है। हमने पांडुलिपियों को अनुमोदित कर दिया है। डा० गोविन्द दास के इस सुझाव कि अहिन्दी भाषाओं की प्रमुख साहित्यिक पुस्तकों को दक्षिण की भाषाओं में प्रकाशित किया जाये मान लिया है और ऐसी पुस्तकें अगले वर्ष प्रकाशित की जायेंगी।

मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का काम इतना संतोषजनक नहीं रहा। किन्तु इस का हाल में पुनर्गठन किया गया है और एक पुर्नविलोकन समिति बनाई गई है, जिसने उसके कार्य का भली प्रकार अध्ययन किया है। हमने भारत, 'भूमि और लोग' नामक पुस्तक माला प्रकाशित करने का निर्णय किया है। इनको लिखने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

अध्यापन के स्तर को ऊंचा करने के लिए हम विशेष प्रयत्न करने का विचार रखते हैं। अध्यापक सारी शिक्षा प्रणाली का केन्द्र है और जब तक उन का स्तर ऊंचा न हो, शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो सकता। अध्यापक शिक्षा के लिए हम बहुत से उपाय करेंगे।

अगले ३ वर्षों में ९ करोड़ रुपये की ऋण छात्रवृत्ति योजना को अगली जुलाई से शुरू किया जायेगा। इसमें अच्छे अच्छे अध्यापक आकर्षित होंगे और १० वर्ष की सेवा के बाद वे ऋण से मुक्त हो जायेंगे और वे शिक्षा के उच्चतम स्तर तक जा सकेंगे।

सदन को ज्ञात है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुधार करने का प्रयत्न किया है। इस समय एक प्राथमिक स्कूल अध्यापक का वेतन १०० रुपये है। हम इसे और भी बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि यदि वे वेतन बढ़ायें, तो केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत सहायता देगी। अन्य उपाय जो हमने किये हैं, उन में तीन लाभ योजना, अध्यापकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय अध्यापक संस्थान इत्यादि हैं।

प्रादेशिक कालेजों में भी हम अध्यापकों को पूरी छात्रवृत्तियां देंगे। उन्हें सरकार से पूरी सहायता मिलेगी ताकि उन्हें कुछ वर्ष तक अच्छा प्रशिक्षण मिल सके। हमें आशा है कि इन प्रादेशिक कालेजों की सहायता से, जिन में रूस और अमेरिका हमारी सहायता कर रहे हैं, हम अध्यापकों के स्तर को काफ़ी ऊंचा कर सकेंगे।

[डा० का० ला० श्रीमाली]

कुछ राज्यों ने ऐसे और कालेजों की मांग की है, किन्तु सीमित संसाधनो के कारण, ये अभी ४ तक ही सीमित रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा की किस्म में सुधार करने लिए हमने कुछ और उपाय किये हैं, जैसाकि अध्यापकों की सेवाओं में प्रशिक्षण । सदन को ज्ञात है कि हमने प्रशिक्षण कालेजों के विस्तार केन्द्र स्थापित किये हैं और अब ११५०० माध्यमिक स्कूल इस विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। शिक्षकों के कालेजों में अध्ययन दल, चर्चाएं आदि, रिफ्रेशर कोर्स आदि आयोजित किये जाते हैं और इससे अध्यापक शिक्षा की नवीनतम गतिविधियों से परिचित रहते हैं। यह प्रयोग बहुत सफल रहा है और इस से प्रोत्साहित हो कर अगले वर्ष प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के कालेजों में भी ३० ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

शिमला के राष्ट्रप्रति भवन में, जोकि हमें दे दिया गया है, हम उच्च अध्ययन की केन्द्रीय संस्था स्थापित करेंगे जहां विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स ग्रीष्म स्कूल आयोजित किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, हमने हिन्दी अध्यापकों के लिए कुछ प्रशिक्षण कालेज स्थापित किये हैं। हैदराबाद में अंग्रेज़ी की केन्द्रीय संस्था खोली गई है। तिरुपति में अध्यापकों को संस्कृत का प्रशिक्षण देने के लिए संस्था खोली गई है। अतः लगभग सभी विषय, प्रविधिक विषय जिनका ख्याल राज्य सरकारें नहीं कर रहीं, केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले लेगी। श्री किशन पटनायक ने कहा है कि शिक्षा मत्रालय ने अवसर की समानता प्रदान करने के लिए कुछ काम नहीं किया और शिक्षा विभागों तथा शिक्षा मंत्रालय को बन्द कर देना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में केवल छात्रवृत्ति योजना का उल्लेख करूंगा।

१९४७ में छात्रवृत्तियों पर कुल खर्च केवल २२ लाख था, किन्तु १९६१ तक हम १९ करोड़ रुपये खर्च करेंगे। सीमित संसाधन होते हुए यह कोई छोटी बात नहीं है। राज्य छात्रवृत्तियों और २४०० राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों और ऋण छात्रवृत्तियों को मिलाकर जोकि लगभग ७०,००० होंगी, ५० प्रतिशत योग्य विद्यार्थी इस में आ जायेंगे । यह एक बहुत बड़ा कदम है। किन्तु अभी हम ने अभी बहुत आगे जाना है। ब्रिटेन में ८० प्रतिशत विद्यार्थीयो को राज्य की ओर से छात्रवृत्तियां मिलती हैं। हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के मामले में आर्थिक ऊंच नीच न रहे, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है। इस कदम से बहुत से गरीब विद्यार्थी, जो पहले उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, अब प्राप्त कर सकेंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि श्री किशन पटनायक अपने आरोप पर पुनः विचार करेंगे।

सदस्यों को याद होगा कि गत वर्ष दिल्ली में डाक द्वारा शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह बहुत उत्साहवर्धक है। विधार्थियों में से बहुत से कम ऐसे हैं, जो छोड़ जाते हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है।

संध्याकालीन कालेजों के बारे में कोठारी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। दिल्ली में ऐसे कालेज हैं किन्तु हम प्रत्येक राज्य में ऐसा एक कालेज खोलने का विचार रखते हैं।

निरक्षरता के प्रश्न पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और राज्यों के सब शिक्षा मंत्रियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा गया है। साक्षरता की प्रतिशतता १९६१ में १६.६१ थी और १९६१ में २३.७। किन्तु निरक्षर लोगों की संख्या १९५१ में ३०११ लाख थी और १९६१ में ३०५० लाख।

इस समस्या का हल के दो तरीके हैं। एक यह है कि प्राथमिक शिक्षा का यथा-संभव शीघ्र से शीघ्र विस्तार किया जाये। दूसरा यह है कि प्रौढ़ निरक्षरता को हटाया जाये। हम ने सब राज्य सरकारों से कहा है कि वे गर्मियों में विश्वविद्यालयों के सब विद्यार्थियों और अध्यापकों को ग्रामों में भेजें। जब तक शिक्षित लोग ग्रामों में न जायें, यह समस्या हल नहीं हो सकती।

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के मामले में, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कालेज स्तर पर सब स्वस्थ विद्यार्थियों को एन० सी० सी० और एन०सी० सी० राइफल्स का प्रशिक्षण देने के लिए पग उठाये जा रहे हैं। एन०सी०सी० को कालेजों में अनिवार्य कर दिया जायेगा। स्कूल स्तर पर राष्ट्रीय अनुशासन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस के लिए नये केन्द्र खोले जायेंगे। दो केन्द्र मेरठ और पंचकुला में खोले जा चुके हैं। इस योजना को सारे स्कूलों के विद्यार्थियों पर लागू किया जायेगा।

श्री किशन पटनायक ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में बोलते हुए कहा था कि इस की स्वायत्तता बहाल की जाये। विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह सच है कि कार्यपालिका परिषद् मनोनीत निकाय है। पिछले सत्र में मैंने एक विधेयक पुरःस्थापित किया था, किन्तु चूंकि आदर्श विधान समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और उसके सुझाव अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के विधानों में सम्मिलित किये जाने थे, जिन्हें अन्य राज्यों ने भी अपनाना था, इस लिए इसे उठा रखा गया था।

श्री हीरेन मुकर्जी ने श्रीनिकेतन में विश्वभारती का उल्लेख किया था। मुझे खेद है कि विश्व-विद्यालय को पिछले कुछ दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। किन्तु मुझे आशा है कि श्री मुकर्जी विद्यार्थियों के कदाचार की निन्दा करेंगे। उपकुलपति को कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी थी। और यह उचित थी क्योंकि उनका व्यवहार बहुत बुरा था मैं यह नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या क्या किया।

यह भी चर्चा की गई थी कि क्या शिक्षा समवर्ती विषय होना चाहिये या राज्य विषय। सलाहकार समिति की पिछली बैठक में अधिकांश सदस्यों ने यह मत प्रकट किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार को अधिक उत्तरदायित्व लेना चाहिये। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, इसको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिकार है और यदि इसके पास पर्याप्त धन हो, तो वह इस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभा सकती है। इस समय कठिनाई धन की है, जो कि न राज्यों के पास है और न केन्द्र के पास। राज्यों ने मंत्रालय के कार्य की सराहना की है। श्री पी० एन० सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है, जो इस बात की जांच करेगी, कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

श्री मुकर्जी ने राष्ट्रीय अभिलेखों का प्रश्न उठाया था। हमने एक समिति नियुक्त की थी। विभिन्न अभिकरणों की राय लेने में कुछ समय लगा है। अब हमें राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो गई हैं और एक विधेयक शीघ्र पुरःस्थापित किया जायेगा। विलम्ब केवल आपातकाल के कारण हुआ है और अभिलेखों को रखने की जगह की कमी के कारण। हमारे पास कोई इमारत होनी

[डा० का० ला० श्रीमाली]

चाहिये, जिस में इन्हें रखा जा सके। मेरे विचार में मैंने सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, जो कि चर्चा के दौरान में उठाये गये थे। मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मंत्रालय के कार्य की सराहना की है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और अगर उचित समझा जाये तो उसका उत्तर दे दिया जाये। गत वर्ष आपने बोलते हुए लोक सभा और राज्य सभा में भी विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम के संबंधमें शिक्षा मंत्रालय को कुछ नीति की घोषणा की थी। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो एक प्रतिक्रियावादी रुख है, उससे आपकी घोषणा बीच में ही रह गई है। अब उस संबंध में क्या आपने कोई निर्णय किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सही नहीं है। जो नीति निर्धारित हुई थी वह नीति करीब करीब सब लोगों ने मंजूर कर ली है। चीफ मिनिस्टर्ज कांफ्रेंस, वाइस चांसलर्ज कांफ्रेंस और अभी हाल में जो इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड मिला था, उन सब ने, जो प्रस्ताव पास किये थे, नैशनल इंटैग्रेशन काउंसिल ने पिछली बार, उनको मंजूर कर लिया है। अब तो सिर्फ प्रश्न यह रहा है कि क्या कदम उठाना चाहिये ताकि हम साहित्य तैयार कर सकें। जो कुछ मैंने ब्यौरा दिया है साहित्य निर्माण करने के लिये वह यह साबित करता है कि जहां तक कंट्रोवर्सी का संबंध है, वह तो खत्म हो गई। अब तो काम करना है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ने आगे एक कदम बढ़ा लिया है।

श्री ओंकाराल बेरवा (कोटा) : बोर्ड से जब किताबें पास हो कर आती हैं तो क्या वजह है कि उनमें गलतियां रह जाती हैं। गलत किताबें निकाल कर बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती हैं, इसका मैं उत्तर जानना चाहूंगा।

डा० का० ला० श्रीमाली : गलती हुई और उसकी जांच भी हुई। सभी ने गलती की मालूम होती है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : बोर्ड में जब पास होती हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१४	शिक्षा मंत्रालय	४०,४१,०००
१५	शिक्षा	१५,४४,५८,०००
१६	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,२६,४९,०००
११७	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	१,४६,०००

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

वर्ष १९६३-६४ के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८१	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . .	३४,२७,०००
८२	पुरातत्व	१,०१,६६,०००
८३	भारत का सर्वेक्षण	३,३१,१८,०००
८४	वानस्पतिक सर्वेक्षण . . .	२५,४६,०००
८५	प्राणिकीय सर्वेक्षण	१८,२०,०००
८६	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य . . .	१६,११,१६,०००
८७	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिककार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५१,६३,०००
१३७	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	२,८१,८३,०००

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के लिये इतना थोड़ा समय निर्धारित किया गया है। चाहे युद्धकाल हो या शांतिकाल किसी राष्ट्र के बिकास के प्रौद्योगिकी विकास की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

युगोस्लाविया के विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर देदीजर ने भारत की वैज्ञानिक गवेषणा के संबंध में प्रतिवेदन दिया है कि यहां की प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया अनसंधान सैद्धांतिक है और उद्योगों के लिये उपयोगी नहीं। सरकार को उद्योगों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य भागों द्वारा अनुसंधान कार्य की प्रेरणा देने का उपक्रम करना चाहिये। हमारे अनुसंधान कार्य में आधुनिक काल के अनुरूप परिवर्तन करना चाहिये और प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक अनुसंधान होना चाहिये। सी० एस० आई० आर० के राष्ट्र के लिये मूलभूत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये अनुसंधान कार्य करना चाहिये।

जेनेवा सम्मेलन में प्रोफेसर ब्लेकेट ने कहा था कि भारत जैसे अर्द्धविकसित देश में अनुसंधान के हेतु अनुसंधान करना बहुत महंगा कार्य है। सी० एस० आई० आर० का कार्य ऐसा ही है।

इस सिलसिले में भारतीय संसद विज्ञान समिति ने जिसके प्रधान प्रधान मंत्री हैं अच्छा कार्य किया है। आशा है यह मंत्रालय इस समिति को सभी सुविधायें प्रदान करेगा।

मैं अनुभव करता हूं कि इस देश में औजार निर्माण का कार्य दो रूप में होना चाहिये अर्थात् नमूने तैयार करना और दूसरे विदेशी नमूनों के प्रतिरूप तैयार करना।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री प्रभात कार]

रसायन और धातु कर्मिक तथा विद्युत् उद्योगों का विकास परामर्शदाता सेवाओं की संस्था द्वारा किया जाना चाहिये । हमें ऊंचे बांधों, महरावी बांधों, कंकरीट के बांधों जैसे नये विषयों के नमूने आदि के नये विषयों का अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिये विशेषीकृत अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने चाहिये । हमारे वैज्ञानिक और औद्योगिक विशारदों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में मात्रा और गुण प्रकार संबंधी सुधार, आपातकाल की आवश्यकतायें पूरा करना, उत्पादन लागत कम करना, आयात कच्चे माल के स्थान पर देशी माल का विकास करना और विद्यमान कच्चे माल का स्तर ऊंचा करना होना चाहिये ।

इंजीनियरों के प्रशिक्षित करने का पाठ्यक्रम ३ वर्ष का होना चाहिये ताकि प्रविधिक कर्मचारी अधिक संख्या में प्राप्त हो सकें ।

हम इंडिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में और वहां के अभिलेखों की फिल्म चित्र तैयार करने के बारे में प्रगति की स्थिति जानना चाहते हैं ।

राष्ट्रीय उद्यान १–१–१९६३ से सरकार के हाथों में आ गया है और मैंने सुना है कि उसे इस प्रकार रखा जा रहा है कि लोगों के लिये आकर्षण की बजाय निकर्षण पैदा हो गया है ।

†डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है । मंत्रालय ने आपातकाल में जो १.८४ लाख रुपया और ३२७ ग्राम सोना दिया है उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । प्रतिवेदन में पूरी जानकारी नहीं दी गई जो कि आपातकाल में आवश्यक थी ।

आजकल युद्ध काल में प्रविधिक कर्मचारियों की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि युद्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत भाग होता है । किन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि इस मंत्रालय ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये कुछ करोड़ रुपये के उपबन्ध छोड़ दिये हैं । यह ठीक नहीं । इस से देश की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती । इस मंत्रालय को अधिक धन मिलना चाहिये ।

प्रतिवेदन में न तो यह बताया गया है कि आपातकाल के लिए अपेक्षित विभागों के लिए प्रविधिक कर्मचारियों के बारे में क्या किया जा रहा है और अनुसन्धान कार्य में कैसी प्रगति की जा रही है ।

इस समस्या का हल करना है कि २७ प्रयोगशालाओं का कैसे उपयोग किया जाये । उनके अनेक अनुसन्धानों का कोई उपभोग नहीं किया गया । इसके लिए कोई प्रयोगात्मक योजना बनानी चाहिये ।

देश में औजारों के निर्माण को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

प्रविधिक शाखाओं में विशिष्टीकृत गवेषणा की अत्यन्त आवश्यकता है । इंजीनियरी तथा अन्य प्रविधिक शाखाओं में स्नातकों के प्रशिक्षण के उपाय किये जायें । वर्तमान कालेजों तथा पालीटैक्नीक संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के इस प्रकार से तय किया जाय कि आपात के कारण बदली हुई परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा कर सकें ।

इसके अतिरिक्त लोगों और संसाधनों के बारे में सर्वेक्षण करने का प्रश्न है जो १० से १५ वर्ष तक होगा । इस सम्बन्ध में यह देखना है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता होगी और प्रतिरक्षा के लिए किस प्रकार का साज सामान तैयार करना होगा । बहुत से उद्योगों का उत्पादन कम है जिसका कारण यह है कि उनमें योजना का अभाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरी आफ साइंटिफिक रिसर्च एण्ड कलचरल अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। टस इमरजेंसी के पीरियड में इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। इस मिनिस्ट्री की सन् १९६२–६३ की रिपोर्ट निकली है उसको मैंने देखा है लेकिन मुझे उस बुकलेट को देखने से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जितनी इनफारमेशन दी जानी चाहिए उतनी इनफ़ारमेशन उसमें नहीं है। बाहर से थोड़ी बहुत जो हमें इनफ़ारमेशन मिलती है और इस किताब को देखने से भी जो हमें मिली है उसके आधार पर मैं संक्षेप में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा।

इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि गये साल में टोटल सैंकशन्ड ग्रांट इस मिनिस्टरी के लिए ३७.७८ करोड़ की थी लेकिन गये साल में ३४.५५ करोड़ रुपये ही खर्च हुए। रिवाइज्ड एस्टिमेट ३४.५५ करोड़ पर ही रक्खा गया। इस तरह से करेंट साल में ३.२३ करोड़ रुपया बचाया। इसके अतिरिक्त आगे सन् १९६३–६४ में भी ४.३२ करोड़ खर्चा कम करना है और इसलिए १९६३-६४ के बजट के वजट ऐस्टिमेट भी ४.३२ करोड़ के हिसाब से कट कर दिये गये हैं। इस तरह से अपने खर्चे में कमी करने की आपने इस रिपोर्ट में विशेषता बतलाई है। लेकिन मैंने देखा है कि इस मिनिस्टरी जितनी लेबोरेटरीज़ हैं, जितने रिसर्च इंस्टीच्यूट्स हैं, उनकी बाबत खाली मेरा ही ऐसा विचार नहीं है कि वे बेकार साबित हो रहे हैं बल्कि कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि **दे आर मेंट फौर लक्जरीज सेक**। उनके बारे में ऐसा ही प्रतीत होता है। एक चावल को देखने से मालूम हो जाता है कि पूरी हांडी कैसी पकी है। इसलिए मैं केवल एक संस्था, नेशनल फ़िज़िकल लैबारेटरी, के बारे में बताना चाहता हूं कि उसमें कितना वैस्ट होता है। उसमें १९ एसिस्टेंट डायरेक्टर्ज़ हैं, जिन पर सोलह सोलह सौ रुपया खर्च होता है। वहां पर अलग अलग वाटर टाइट कम्पार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिनका आपस में कोई सम्पर्क या सम्बन्ध नहीं है और जो एक दूसरे के इन्स्ट्रूमेंट्स आदि काम में नहीं ला सकते हैं; उन लोगों को कोई प्राबलम्ज़ नहीं दिए गए हैं। क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि पिछले दस सालों में उनको कौन कौन से प्रालम्बज़ दिये गए हैं और उन्होंने कितने पेटेन्ट प्राप्त किये? इस पुस्तिका से मालूम होता है कि उन्होंने तेरह या चौदह पेटेन्ट प्राप्त किये। सोलह कुकर का एक पेटेन्ट जीवनलाल ने लिया हुआ है। वह सोलर कुकर वैसे ही सूरज में हवा खा रहा है। उसको काम में लाने और उससे फायदा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

वहां पर जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, उससे हमारी इण्डस्ट्रीज़ को कोई फ़ायदा होता है या नहीं, इस तरफ हमारे शासन या मिनिस्टर साहब को कोई ध्यान नहीं है। वहां पर इतना वैस्ट होने के बावजूद हम देखते हैं कि पहले जो ट्रेंचिज खोदी गई थीं और तावदानों पर, ग्लासपेन्ज़ पर, जो काग़ज़ लगा दिये गए थे, इमर्जेंसी ख़त्म होने के बाद उन ट्रेंचिज़ को भरा जा रहा है और उन काग़ज़ों को हटाया जा रहा है। वहां पर सैकण्ड बार का मैटीरियल बाहर वैसे ही पड़ा हुआ है। उस मैटीरियल को कभी काम में नहीं लाया जाता है और न ही उसका सेल किया जाता है। एक चौकीदार वहां पर रखा हुआ है। बड़े बड़े महत्वपूर्ण इंस्ट्रुमेंट्स और रेडार वगैरहा वहां पर पड़े हुए हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब या मंत्रालय का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है।

वहां पर जो स्कालर्ज काम करते हैं, उन में से कुछ मध्य प्रदेश से आते हैं और कुछ गुजरात से। अगर कभी उन से बात होती है, तो वे कहते हैं कि उन की जाब्ज में सिक्योरिटी नहीं है और तीन चार साल काम करने के बाद भी उन को जाना पड़ता है। उन का कहना है कि उन की जाब्ज की सिक्योरिटी न होने, वहां पर वाटर-टाइट कम्पार्ट्स् होनेऔर उन के सामने कोई प्रावलम्ज न होने के कारण रूपया वेस्ट हो रहा है और फिजूल खर्च हो रहा है।

लेह और मिसामारी में डिफेंस के संबंध में लैबोरेटरी खुली हुई ह, जिन पर चार चार लाख रूपया खर्च होता है। शायद मिनिस्टर साहब को उन के बारे में मालूम नहीं है। वहां से स्कालर्ज वहां

[डा० मालकोटे]

पर रखे भेजे जाते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर डिफेंस इण्डस्ट्रीज़ और रिसर्च लैबारेटरीज़ में को-आर्डिनेशन किया जाये और उनको प्रावलम्ज़ दी जायें तो इमर्जेंसी पीरियड में बहुत फ़ायदा होगा और जनता यह महसूस करेगी कि इस काम पर जो इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, वह उचित और ठीक है।

इस बुकलैट के अन्त में २९ नेशनल लैबारेटरीज़ और इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी गई है। हम यह जानना चाहेंगे कि इन को कौन कौन सी प्राब्लम्ज़ दी गई हैं, इन्होंने कितना मैटीरियल बाहर निकाला है, इनसे इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा हुआ है और इन्होंने कितने पेटेन्ट्स प्राप्त किये हैं। इस बुकलैट में इस बारे में कोई इन्फर्मेशन नहीं दी गई है। पालियामेंट के मेम्बर्ज़ के नाते हम लोगों को यह सूचना मिलनी चाहिए, ताकि हम जनता को यह बता सकें कि इन संस्थाओं पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है, उसका क्या औचित्य है और उससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है।

दूसरे देशों में इन्वेन्टर्ज़ क्लब्ज़ होते हैं, जिनमें सब साइंटिस्ट्स एक जगह मिल कर बैठते हैं और किसी एक प्राबलम पर चर्चा और विचार विनिमय करते हैं। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर मिनिस्टर साहब यहां पर भी इन्वेन्टर्ज़ क्लब चलाने का प्रस्ताव करेंगे, तो उस को बहुत फ़ायदा होगा।

हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे यहां जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च स्कालर्ज़ हैं, उनसे जनता को, सर्व-साधारण को, क्या फ़ायदा पहुंचता है। रिपोर्ट के पेज ३ पर लिखा है कि मई-जून, १९६२ में मिनिस्ट्री आफ साइंटिफिक रिसर्ज एण्ड कल्चरल एफेयर्स के एक्स-सैक्रेटरी, प्रोफ़ेसर एम० एस० थाकर, जैनेवा गए। क्यों? लैस डेवेलप्ड एरियाज़ के बैनिफिट के बारे में डिस्कशन करने। इसके बाद वह अक्तूबर, १९६२ में फिर इसी काम के लिए जेनेवा गए। चार पांच महीने में दो बार जेनेवा जाना क्या लग्ज़री नहीं है, ग़रीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे गांवों में बुलाक कार्ट को खींचने के लिए जो तकलीफ़ होती है, उसको दूर करने के लिए उसमें बाल-बीयरिंग लगाने, घानी को ज्यादा आसानी से चलाने और इसी प्रकार दूसरी छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज को ज्यादा अच्छी तरह से चलाने के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये बातें जानने के लिए उन को जेनेवा में क्यों भेजा गया? अगर मई में उनके दिमाग़ में यह बात नहीं आ सकी, तो अक्तूबर में फिर जाने से क्या फ़ायदा हुआ?

जहां तक विज्ञान मन्दिर स्कीम का सम्बन्ध है, इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी नित्य प्रति की कृषि समस्याओं सम्बन्धी वैज्ञानिक सिद्धान्तों से अवगत कराना है। इस "एटसैटरा" में बहुत से बातें आ जाती हैं, लेकिन जहां जहां से हम लोग आते हैं, वहां तो इन संस्थाओं के बारे में हम को कुछ नहीं मालूम होता है। केवल डेकोरेशन के लिए और लोगों में प्रचार करने के लिए सब २९ इंस्टीट्यूट्स और लैबारेटरीज़ आदि दिल्ली में रखी हुई हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली में जो स्कालर्ज़ आते हैं, उनके बैठने और रहने के लिए जगह नहीं है। उनके लिए बहुत डिफ़ी-कल्टीज़ हैं। उनको अपने प्रदेशों को छोड़ कर यहां आना पड़ता है। आखिर दिल्ली में इन सब संस्थाओं को रखने की क्या आवश्यकता है? यदि इन संस्थाओं को सारे देश के भिन्न भिन्न भागों में रखा जाये, तो ज्यादा अच्छा होगा।

सरकार टैक्निकल नालेज फैलाने के लिए स्कूल खोलना चाहती है और इसके लिए वह टैक्निकल बोर्डज़ बनाना चाहती है। लेकिन वे टैक्निकल बोर्डज़ कहां कहां बनाए जायेंगे, इसका विवरण नहीं दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और कई दूसरी स्टेट्स में टैक्निकल एजूकेशन और पालिटैनीक एजूकेशन की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन इस बारे में ओपन-एयर पालिसी अपनाई गई

है, अर्थात् अगर जनता तीन लाख रुपया दे, तो वहां पर पालिटैक्नीक खोला जायेगा। शासन को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

चाइना से लड़ाई शुरू हुए छः महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे स्कालर्ज़ ने एक जगह पर बैठ कर इस बात पर विचार नहीं किया है कि इस देश की डिफ़ेंस प्राबलम्ज़ क्या हैं। अब उनको इस बात का ख्याल आया है। अब पूना में कुछ स्कालर्ज़ यह विचार कर रहे हैं कि हमारी डिफेंस प्राबलम्ज़ क्या हैं। माननीय मन्त्री जी इस बात की तरफ ध्यान दें कि हमारे देश को जिन बातों की जरूरत है, उनके बारे में रिसर्च की व्यवस्था की जाये। अगर देश के जन-साधारण की प्राब्लम्ज़ और डिफ़ेंस की प्राबलम्ज़ को हल करने के बारे में रिसर्च की जायगी, तो उस पर किया जाने वाला ख़र्च उचित समझा जायेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि ब्लैकेट ने कहा है, फ़ंडामेंटल रिसर्च को यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया जाये और यह मन्त्रालय उन प्राबलम्ज़ को हाथ में ले, जिनका सम्बन्ध देश की डे टु डे लाइफ़ और देश के डिफ़ेंस से है। इन इंस्टीट्यूशन्ज़ को एप्लाइड साइंस की तरफ़ ध्यान देना चाहिए और फ़ंडामेंटल रिसर्च पर पैसा नहीं ख़र्च करना चाहिए। वह काम यूनिवर्सिटीज़ अच्छी तरह से कर सकती हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८२	१	श्री बड़े . .	अर्द्ध-स्थायी क्लर्कों की छटनी।	१०० रुपये
८६	३	श्री बड़े . .	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की अव्यवस्था।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू और कश्मीर) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे प्रसन्नता है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालायें स्थापित कर दी गई थीं।

हमें ऐसे उपाय करने चाहियें कि विदेशों में हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वे देश में लौट आयें। यहां उनकी सेवा की दशा को सुधारना चाहिये।

हमारे विज्ञान विभाग में बहुत सी निराशाजनक बातें हो रही हैं। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। ऐसा सुनिश्चित करना चाहिये कि वैज्ञानिक स्वतन्त्रता से काम कर सकें। उन्हें प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपना चाहिये ताकि वे अपना मन केवल गवेषणा कार्य में लगा सकें।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शामलाल सर्राफ़]

हमारी प्रयोगशालायें पिछले १५ वर्ष से काम कर रही हैं किन्तु कृषि में अनुसंधान का कहां तक प्रयोग किया गया है ? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कृषि और उद्योग में अनुसंधान कार्य का उपयोग किया जा सके ।

पंच वर्षीय योजनाओं के कारण हजारों औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई है किन्तु क्या बाहर से मंगाये गये प्रविधिक पर विश्वास किया जा सकता है ? मंत्रालय को व्यवस्था करनी चाहिये कि सभी स्तरों पर काफी संख्या में लोग प्रशिक्षित किये जायें जो औद्योगिक एककों में सेवा कर सकें । हमें सदा विदेशी वैज्ञानिकों पर निर्भर नहीं करते रहना चाहिये ।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय अधिकाधिक इंजीनियर और प्रविधिक पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है ऐसे निकाय स्थापित करने चाहियें जो परियोजनाएं तयार किया करें ।

†**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : कुछ वर्ष हुए विदेशी वैज्ञानिकों ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिस में कहा गया था कि हमारी प्रयोगशालाओं के उपकरण अच्छे नहीं हैं ।

विदेशों से आने वाले हमारे कितने वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय पजी में नाम लिखवाये हैं यह सच है कि उनमें से बहुत सों को विदेश में सेवा करनी पड़ती है । सरकार को चाहिये कि वह उन्हें वही वेतन दे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दे रही है ।

विदेशी वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिये कि हमारे विश्वविद्यालयों में भाषण दें ।

मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये एटलस विदेशों में भी उपलब्ध करवाने चाहियें । प्रतिवेदन में एवरेस्ट अभियान की उपलब्धियों का क्यों उल्लेख नहीं किया गया ?

महिलाओं के लिये अधिक संख्या में प्रविधिक संस्थाएं खुलनी चाहियें ।

यदि राजकीय अकादमियों को केन्द्रीय अकादमी से सम्बन्ध किया जाय तो बहुत कुछ दोहरापन समाप्त हो सकता है और धन की बचत हो सकती है ।

मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं का तस्कर व्यापार बन्द करने की व्यवस्था करनी चाहिये । आश्चर्य है कि सीमा शुल्क अधिकारी इसे नहीं रोक सके । दूर स्थित मंदिरों से मूर्तियां चुराई गई हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

ऐतिहासिक नगरों की निर्माण सम्बन्धी सुन्दरता को अनुक्षुण्य रखने का प्रयत्न करना चाहिये ।

भारत के राष्ट्रीय अजायबघर के लिये मैं सरकार को सलाह देती हूं । शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता के लिये धन देने के लिये भी मंत्रालय श्रेय का पात्र है ।

†**श्री करुथिरमन** (गोबी चेट्टिपलयम) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

स्वतन्त्रता के उपरांत ही देश में अनुसंधान कार्य आरम्भ हुआ है किन्तु दूसरे देश हमारा मूल्यवान साहित्य बाहर ले गये हैं जिससे वे लाभप्रद अनुसंधान कर रहे हैं ।

पुरातत्व विभाग ने महाकवि कम्बन के जन्म स्थान की रक्षा हेतु केवल एक बाढ़ बना दी है । यह पर्याप्त नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वनस्पति और प्राणिकीय विज्ञान के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई। हमें अपने साहित्यिक ग्रंथों में भी विज्ञान सम्बन्धी बहुत सामग्री मिलती है जिसका अनुसधान करना चाहिए कम्पन जैसे महाकवि ने दसवीं शताब्दी में यह लिख दिया था कि अणु को खंडित नहीं किया जा सकता कम्पनने आज के स्पूतनिक की बात भी रामायण में कह दी थी कि ऊपरी सिंध में से गुजरा जा सकता है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय में कम्बा रामायण पर गवेषणा की जा रही है। कम्बा के जन्म स्थान पर स्मारक को पत्थरों आदि की दीवार से सुरक्षित नहीं किया गया। कम्बा के छात्रों को गवेषणा की सुविधायें दी जानी चाहियें।

संगीत अकादमी और राज्यों को आवंटित राशि का लाभ केवल नगर-क्षेत्रों को ही होता है, ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं। संस्कृति का स्तर उन्नत करने के लिये आवश्यक है कि आवंटित राशि ग्रामीण-क्षेत्रों में भी व्यय की जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इस महान कवि के स्मारक को सुरक्षित रखा जाय और इस कवि पर अनुसंधान का कार्य आरम्भ किया जाये।

†**श्री शिवमूर्त्तिस्वामी** (कोप्पल) : श्रीमान्, मुझे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय। मैं पहले उपस्थित नहीं था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, वह समय अब समाप्त हो चुका है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : हमने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं की। चीन के आक्रमण के पश्चात् हमें अपनी इस भूल का आभास हुआ। इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय मैंने कहा था कि इसके पुनर्नवीकरण की आवश्यकता है किन्तु अभी इस विषय की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

देश की विज्ञान संबंधी योजना दोषयुक्त है। हमारे यहां विज्ञान के क्षेत्र में प्रशासनिक नौकरशाही है और ऐसे वातावरण में विज्ञान उन्नति नहीं कर सकता। इसके लिये स्वतन्त्र वातावरण की आवश्यकता है। प्रशासकों के हांथों में सभी शक्तियां हैं और जो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक गवेषणा में व्यस्त रहना चाहते हैं वह क्षुब्ध हो उठते हैं। प्रोफेसर चन्द्रशेखर ने, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, और जो अब अमरीका में हैं, कहा है कि भारत में विज्ञान की अवस्था निराशा जनक है। इसका कारण यह है कि समाज में वैज्ञानिकों की स्थिति सुनिश्चित नहीं है। प्रधान मंत्री ने विदेशों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों से स्वदेश लौट आने की अपील की थी, किन्तु केवल अपील से कुछ नहीं होता। यहां उन्हें पर्याप्त वेतन और उचित वातावरण उपलब्ध नहीं है।

हमने विज्ञान के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री प्रकाशित की है किन्तु हमने इसके लिये कोई क्रम-बद्ध योजना नहीं बनाई है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है। इसलिये विज्ञान हमारे लिये बहुत आवश्यक है। इस देश में वैज्ञानिक प्रतिभा की भी कमी नहीं है किन्तु उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता। प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि हमारे अधिकतर वैज्ञानिक गवेषणा के स्थान पर प्रशासनिक कार्यों में अधिक लगे हुए हैं। श्री हुमायू कबिर ने भी एक बार कहा था कि एक वैज्ञानिक था जो ११० समितियों का सदस्य था। जब हमारे वैज्ञानिक इतनी समितियों के सदस्य बना दिये जाते हैं तब अवश्य ही विज्ञान की प्रगति में रुकावट होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

हमने १९६० में ६,३६३ गवेषणा संबंधी प्रकाशन निकाले थे और इनकी संख्या देख कर यही प्रतीत होता है कि हमने काफ़ी प्रगति की है, किन्तु ऐसा नहीं है।

इस देश में वैज्ञानिक गवेषणा और उद्योग में भी समन्वय नहीं है। उदाहरणार्थ मार्च १९६२ तक राष्ट्रीय विकास निगम के पास ५२७ आविष्कार आये थे जिनमें से केवल १५६ ही बेचे गये। एक वैज्ञानिक को एक आविष्कार करने के पश्चात ही अपना कार्य बन्द नहीं कर देना चाहिये इसके कार्य करने की अन्तिम अवस्था तक उसकी जांच करनी चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि मंत्रालय हमारे प्राविधिकों के प्रशिक्षण के लिये कुछ व्यवस्था कर रहा है। ६,००० व्यक्तियों को डिप्लोमा कोर्स और ३,००० व्यक्तियों को डिग्री कोर्स में शिक्षित करने की व्यवस्था है। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि इनको शिक्षा मौजूदा इंजीनियरिंग कालेजों में ही होगी। किन्तु इन संस्थाओं में पहले ही विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक कम हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस अन्तर में और अधिक वृद्धि न हो।

माननीय मंत्री ने कुछ समय पूर्व स्वीकार किया था कि देश में बहुत अधिक बौद्धिक अपक्षय हो रहा है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार हमारी योजना के प्रथम दो वर्षों में डिप्लोमा कोर्स में ५५ प्रतिशत और डिग्री कोर्स में ३५ प्रतिशत अपक्षय हो रहा है। इसे रोकने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये।

लन्दन स्थित भारतीय पुस्तकालय का मामला भी बहुत दिनों से खटाई में पड़ा है। हाल ही में राष्ट्रमंडलीय संबंधों के ब्रिटिश अवर सचिव श्री जोन टिल ने जो एक वक्तव्य में कहा था कि यह पुस्तकालय ब्रिटेन का है। मैं नहीं जानता कि इस पर आपत्ति की गई है अथवा नहीं।

प्रतिवेदन के अनुसार भारी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यिक साँस्कृतिक कार्यक्रम हुये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कुछ सीमित दायरे में ही किये गये हैं आज जनता को वह उपलब्ध नहीं हो सका है।

अन्तर्राज्यिक कार्यक्रमों में अधिक तेज़ी लायी जानी चाहिये। आज चीनी आक्रमण के कारण देश में एकता उत्पन्न हो गयी है। किन्तु यह एकता अस्थायी है। चीनी आक्रमण का संकट समाप्त हो जाने पर पुनः विघटनकारी कार्यवाहियाँ आरम्भ हो सकती हैं। इसलिये इस एकता को स्थिर बनाने की आवश्यकता है। इसके प्रयोजन की पूर्ति के लिये अन्तर्राज्यीय साँस्कृतिक कार्यक्रमों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में एक शिकायत यह है कि यह साँस्कृतिक दल किसी राज्य में जाकर एक या दो प्रदर्शन करते हैं किन्तु उन्हें वहाँ जनता से मिलकर उनके रीति-रिवाज, साँस्कृतिक विशेषतायें आदि के अध्ययन करने का अवकाश नहीं मिल पाता। यदि आप चाहते हैं कि इन कार्यक्रमों से कोई प्रयोजन सिद्ध हो तो इन लोगों को उस स्थान के निवासियों से जहाँ यह अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, खुले रूप से मिलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

मैं २४ नवम्बर को श्री कामत के साथ इलाहाबाद गया था और हमने ३–४ सभाओं में भाषण दिया। किन्तु हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि श्रोताओं में महिलाओं का अभाव था। मैंने मेरे एक स्थानीय मित्र से इस सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने यह उत्तर

दिया कि यह मुगल परम्परा है और हम अब भी इसका पालन करते हैं। किन्तु इस प्रकार की परम्परा को, पृथक्करण और कूपमंडूकता की परम्परा को समाप्त कर देना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री च० का० भट्टाचार्य।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् इस मंत्रालय का कार्य विज्ञान और संस्कृत में, नये और पुराने में संबंध स्थापित करना है और इसकी सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि यह कहाँ तक इस कार्य में प्रगति करता है।

महारानी गायत्री देवी ने कुछ अमूल्य कलाकृतियों के संग्रह और उनकी तस्करी के सम्बन्ध में उल्लेख किया था। कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के बहुत से घरानों में ऐसी कलाकृतियाँ हैं, किन्तु जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद अब वह उन्हें अपने पास बनाये रखने में असमर्थ हैं और वह तेज़ी से नगण्य मूल्य पर उन्हें बेच रहे हैं। बर्दमान राज्य घराने की भी कलाकृतियाँ बाज़ार में बिकती हुई देखी गयी हैं। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि वह बंगाल के और शेष भारत के प्रचीन घरानों से संपर्क स्थापित करें और जिन कलाकृतियों को वह अपने पास रखने में असमर्थ हों उन्हें उनसे खरीद कर कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास आदि की राष्ट्रीय आर्ट गैलेरी में रखवाने की व्यवस्था करें।

मैं आप को यह भी बताउंगा कि इनकी तस्स्करी किस प्रकार की जाती है। यह आम तस्कर व्यापारियों द्वारा ही नहीं अपितु प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी की जाती है। साहित्यिक क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त एक महिला एक बार कलकत्ता आयी और उन्होंने अमूल्य कलाकृतियों के अध्ययन के सम्बन्ध में इन घरानों से संपर्क स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी गयी। वह प्रतिदिन इन कलाकृतियों को देखने आतीं और अपने थैले में कोई न कोई वस्तु रख कर ले जाती। उसके साथ वाले चौकीदार ने इस बात की खबर स्वामियों तक पहुंचा दी। अगले दिन जब वह फिर यह कार्य कर रही थी तब उसे पकड़ लिया गया और उससे कुल वस्तुयें वापिस ली गयीं।

फिलाडेल्फिया के संग्रहालय में एक दक्षिण भारतीय मंदिर का संपूर्ण अग्र भाग रखा हुआ है। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में एक अध्याय 'विदेशी सांँस्कृति संबंधी' के विषय में है। मेरा सुझाव है कि इस में एक और अध्याय "भारत के बाहर भारतीय संस्कृति का अध्ययन" जोड़ लिया जाये। समस्त दक्षिण पूर्व एशिया में आपको भारतीय संस्कृति के परिचायक दृश्य देखने को मिलेंगे। मैंने कम्बोडिया की राजधानी में घूमते हुए यह देखा कि वहाँ की सड़कों के नाम भारतीय भाषा में हैं। एक सड़क का नाम "पुष्पवीथि" था। यह कलकत्ता अथवा दिल्ली की सड़कों के नामों से अधिक मधुर था। यहाँ अभी अध्ययन किया जाना चाहिये। यदि इन जानकारियों का संग्रह किया जाये और उन्हें सुरक्षित रखा जाये तो भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय तैयार हो जायेगा।

माननीय मंत्री ने कहा था कि शिक्षा का स्तर स्थायी रूप से नीचे नहीं गिराया जायेगा। मेरा तो सुझाव यह है कि अल्पकाल के लिये भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन में छात्रों को छुट्टियों में रोजगार दिलाने का भी उल्लेख है। मैं निवेदन करता हूं कि इस संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

मैंने वर्तमान प्रतिवेदन की पिछले प्रतिवेदन से तुलना की । पिछले प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि रूस को ७ टैगोर छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करा दी जायेंगी। किन्तु इस प्रतिवेदन से पता चला है कि कुल ६ छात्र वृत्तियाँ ही दी गयी हैं। सातवीं का क्या हुआ यह माननीय मंत्री वादविवाद का उत्तर देते समय बताने की कृपा करेंगे ।

गज़ेटियर का पहला भाग प्रेस में भेजा जा चुका है । दूसरा भाग भेजा जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इसे सावधानीपूर्वक देख कर भेजा जायेगा, जिससे पहले भाग की तरह इसमें अशुद्धियाँ होने की सम्भावना न रहे ।

वनस्पति विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण कलकत्ते के विभिन्न भागों में किया जा रहा है। इसके स्थान पर यदि एक ही भाग में किया जाता तो अधिक अच्छा होता ।

लन्दन स्थित भारतीय पुस्तकालय के संबंध में मेरा यह मत है कि यदि उसके बंटवारे की नौबत आजाये तो इससे यही अच्छा होगा कि वह लन्दन में ही बना रहे ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिवेदन अधिक ज्ञानवर्धक नहीं है। न तो यह उत्साहवर्धक है न ही प्रभावोत्पादक मेरे मत में तो यह नीरस ही है। मैं माननीय मंत्री से आशा करूंगा कि वह संसद के समक्ष माँगों को रखते समय इस बात पर व्यक्तिगत ध्यान दिया करें। क्योंकि यह अच्छा है कि संसद के सम्मुख कार्य, कार्य करने की पद्धति और कठिनाइयों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखी जाये।

मैं मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही इस बात पर खेद प्रकट करता हूं कि मंत्रालय ने अनुमानित आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने में संकोच से काम लिया है । इस मंत्रालय के प्रसार के लिये पर्याप्त क्षेत्र है और इस का कार्य देश के लिये इतना हितकारी है कि यदि अधिक माँगें भी रखी जातीं तो भी संसद् उन्हें स्वीकार कर लेता । यह सच है कि आजकल आपातकाल है और हमें हर क्षेत्र में मितव्ययिता करनी है किन्तु सरकार स्वयं वैज्ञानिक गवेषणा और साँस्कृतिक कार्य क्षेत्र में कोई बडा कार्यक्रम तैयार करने में झिझक रही है।

सरकार ने वैज्ञानिक गवेषणा के क्षेत्र में बहुत कम प्रगति की है। इसके बहुत से कारण हैं। हम अधिकतर दूसरे राष्ट्रों की गवेषणाओं और तकनीकी जानकारी पर कार्य कर रहे हैं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की निन्दा नहीं करता। वह लाभदायक है। किन्तु खेद तो इस बात का होता है कि हम अपने देश में यह कार्य नहीं कर सकते। मैं मूल गवेषणा और व्यावहारिक गवेषणा के कल्पित विभेद को नहीं उठाना चाहता। सरकार का यह रुख कि मूल गवेषणा हमारे राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण है बिल्कुल ठीक है ।

हमारे देश में मूल गवेषणा और तकनीकी प्रयास दोनों में अधिक उन्नति नहीं हुई है। कुछ व्यक्तिगत सफलताओं को छोड़ कर इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। माननीय मंत्री इस का प्रतिवाद यह कह कर कर सकते हैं कि आखिर १५-१६ वर्षों में हम और क्या कर सकते थे। किन्तु मैं तो यह कहता हूं कि अभी उसका उचित प्रकार से आरम्भ ही नहीं किया गया है।

जो लोग तकनीकी प्रयत्नों पर जोर देते हैं वह यह समझते हैं कि वैज्ञानिक गवेषणा बच्चों का खेल है। मेरा मत तो यह है कि वैज्ञानिक गवेषणा की संपूर्ण प्रगति एक साथ होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यावहारिक प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में भी हम ने विशेष कार्य नहीं किया है। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यों के क्षेत्र में नौकरशाही का बोलबाला है। जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाता तब तक हम अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे।

प्रौद्योगिकी में हम ने उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है, केवल इसी से यह प्रतीत होता है कि हमारे यहां क्रियात्मक और कल्पनाप्रधान कार्यप्रणाली का अभाव है। जब तक हम इस क्षेत्र में महान् आविष्कार नहीं करते तब तक हमारा देश जो सैकड़ों वर्षों से पिछड़ा हुआ है, प्रगति नहीं कर सकता। इस उद्देश्य के लिये माननीय मंत्री को चाहिये था कि इस क्षेत्र में गवेषणा करने के लिये बड़े कार्यक्रम बनाये जाते और अधिक अनुदानों के लिये सभा की अनुमति मांगी जाती।

सांस्कृतिक कार्यों के अन्तर्गत बहुत से विषय आ जाते हैं। कोई भूल-चूक हो जाने पर इस बात की आड़ लेने में सुविधा होती है कि इस का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। संस्कृति को मनोरंजन का रूप दिया जा रहा है। मेरा एक प्रश्न है। संस्कृति क्या है? क्या इस ने हमें जीवन में निहित सौन्दर्य का दिग्दर्शन कराया है? क्या इस ने हमें प्राचीन कला का अनुभव करने में समर्थ बनाया है? क्या इस ने हमें रचनात्मक बनाने में योग दिया है? मैं समझता हूं इन सब का उत्तर नहीं में होगा।

इस मंत्रालय के लिये और इस मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाली बहुत सी अकादमियों के लिये एक विस्तृत कार्य-क्षेत्र है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण भी इन अकादमियों के कार्य में बहुत बाधा उत्पन्न होती है।

देश में बहुत सी अप्रकाशित पाण्डुलिपियां हैं। सरकार को चाहिये कि उन्हें प्रकाशित करवाये।

मंत्री महोदय को चाहिये कि इस देश की और विदेशों के विश्वविद्यालयों में की जाने वाली गवेषणाओं को माइक्रोफिल्म्स उपलब्ध करावें।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह यह बतायें कि प्रादेशिक भाषाओं के विकास के सम्बन्ध में उनकी क्या योजनायें हैं? क्योंकि प्रतिवेदन के २१वें पृष्ठ पर इस विषय में जो कुछ कहा गया है वह पर्याप्त नहीं है। हम उन से यह कहने की आशा करते हैं कि वह प्रादेशिक भाषाओं की एक अखिल भारतीय संस्था बनाने जा रहे हैं। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सिंधी भाषा के विकास के लिये भी, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, प्रयत्न किया जा रहा है। मैं उन से निवेदन करता हूं कि राजस्थानी भाषा के विकास के लिये भी प्रयास किया जाये।

मैं उन्हें कालिदास के स्मारक के और इस देश में इंडोलोजी की संस्था स्थापित करने के विषय में भी स्मरण दिला देना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम काफी मात्रा में सामाजिक विधान बना रहे हैं और सामाजिक संस्थायें स्थापित कर रहे हैं; किन्तु इन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये कोई सरकारी मंत्रालय अथवा विभाग नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक सामाजिक कार्य मंत्रालय भी खोल दिया जाये।

डा० ताराचन्द की पुस्तक "स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास" को तैयार करना बन्द कर दिया जावे क्योंकि यहां के और विदेशों के विद्वानों ने इस विषय में अत्यन्त आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी ।

श्री बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो महकमा है इस का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन काम कितना बड़ा है, इस का पता नहीं । अहमियत तो इस को बहुत दी जाती है कि यह बड़ा अहम महकमा है, बहुत बड़ा महकमा है, लेकिन मेरे खयाल में इस पर विचार के लिये समय सब से कम दिया गया है । यह महकमा बड़ा किधर से है इस का पता नहीं ।

यह ठीक है कि आज के दौर में जब कि देश के ऊपर आपत्ति है, ऐसे दौर में जिस के अन्दर विज्ञान के बगैर, कल्चर के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता या तरक्कीयाफ्ता मुल्कों के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे वक्त के अन्दर जब कि दूसरे मुल्कों के साइंसदां चांद और सितारों तक पहुंच रहे हैं, उस में यह हमारी रिसर्च जो है, उस के सम्बन्ध में मैं क्या बतलाऊं ? वह रसातल की तरफ जा रही है, आकाश की तरफ नहीं जा रही है ।

चूंकि समय बहुत कम है, मैं आंकड़े तो नहीं दे सकता, इसलिये मैं आप की मार्फत मिनिस्टर साहब के सामने और सदन के सामने सिर्फ इस मिनिस्ट्री में हो रहे भ्रष्टाचार की तरफ तवज्जह दिलाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भ्रष्टाचार बतलाने का समय नहीं है ।

श्री बागड़ी : मैं इसी महकमे के भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं । अगर इस समय इस का भ्रष्टाचार नहीं बतलाऊंगा तब कब बतलाऊंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसी मिनिस्ट्री के बारे में ?

श्री बागड़ी : जी हां, इसी मिनिस्ट्री के भ्रष्टाचार के बारे में, न अपने बारे में और न और किसी के ।

अर्ज यह है कि इस मिनिस्ट्री के बारे में यह बड़ी मशहूर कहावत है कि इस में चाचा, भतीजा और रिश्तेदारवाद बहुत चलता है, जातिवाद, प्रान्तवाद और रिश्तेदारवाद बहुत चलता है । जिस महकमे में यह बात आ जाती है, उस के अन्दर लियाकत, काब्लियत की कोई तमीज और लिहाज नहीं रहती । अगर इस तरीके से कर्मचारियों का चुनाव होता है तो वह तबाही की तरफ जाता है, तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि वह लियाकत को नहीं पूछता है, वहां पर सिफारिश चलती है, लिहाज और मुलाहजा चलता है । एक तो इस महकमे के अन्दर सब से बड़ी बात यह है ।

दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि इस महकमा के अन्दर जो एक लेबोरेटरी है उस के लिये डाइरेक्टर नहीं मिला । मैं एक सजेशन मिनिस्टर साहब के सामने देना चाहता हूं कि डाइरेक्टर्स की कमी तो होगी लेकिन मिनिस्टर्स की कोई कमी नहीं है । एक मिनिस्टर बढ़ा दीजिये इस लेबोरेटरी के लिये । शायद आप का काम पूरा हो जाय क्योंकि काबिल लोग तो डाइरेक्टर बनने के लिये मिलने वाले हैं नहीं ।

इस के बाद मैं इस महकमे के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । असारे कदीमा इस महकमे का अंग है ।

एक माननीय सदस्य : उस की दुरुस्ती के लिये काबिलियत की जरूरत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : बोटों की जरूरत है । मैं अर्ज करूंगा कि असारे कदीमा जो ताजमहल है जो दुनिया में सब से सुन्दर चीज है, जिस की सुन्दरता को कायम रखना हिन्दुस्तान का गौरव था, उस की जो मरम्मत करवाई गई या जो देख भाल के लिये पैसा लगाया गया, उस ने पहली खूबसूरती को भी बदसूरती में तब्दील कर दिया । वहां के पुराने संगमरमर के पत्थरों को, जो उसी में से टूट फूट कर निकले थे, उन्हीं को तोड़ फोड़ कर लगा दिया और नये संगमरमर का पैसा ले लिया । पहले वहां मरम्मत के लिये छः इंच कंक्रीट का प्लैन दिया था, लेकिन वहां पर ३ इंच की कंक्रीट लगाई गई । इस तरह से वहां पर कितने पैसे का भ्रष्टाचार हुआ इस का पता नहीं ।

इस के बाद लेबोरेटरीज के बारे में और जो इन्स्टिट्यूट हैं उन के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी चीजें अर्ज करूंगा जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है । और तो मैं क्या कहूं, सब से बड़ी बात यह है कि जितने इन्स्टिट्यूट हैं उन के अन्दर से बड़े बड़े अफसर लोग, यहां तक कि यहां के बड़े बड़े मिनिस्टर साहब भी चीजें मंगवाते हैं । मेरे पास एक रेकार्ड है, जो कि मैं आप के सामने रख रहा हूं । यहां बैटरी प्लेट्स बनती हैं । उन प्लेटों को मिनिस्टर साहब ने मंगवाया अपने घर के लिये लेकिन उन की रकम नहीं दी गई । उस के बाद आडिटर साहब ने नोट दिया कि यह रकम श्री हुमायून् कबिर से वसूल की जाय । यह अक्तूबर, १९६० का आर्डर है, पता नहीं वह रकम दी गई है या नहीं, या कि वह हुक्म खते में चला गया । जो आडिटर का नोट है यह उस की फोटो है, अगर मिनिस्टर साहब देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

इस के बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि इस महकमे के मातहत काफी सामान बनता है । यह आम चर्चा है कि यहां पर जो रेडियो बनाने का सामान होता है वह जो इस महकमे के बड़े बड़े अफसर हैं उन के घर मुफ्त बन कर जाता है, सेक्रेटरीज के घर रेडियो मुफ्त जाता है । अफसर जो हैं उन्होंने अपने अपने घरों के अन्दर छोटी छोटी फैक्ट्रियां बना रखी हैं, प्लैनिंग बना रक्खी हैं, यहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी इन्स्टिट्यूट के हैं उन के घरों पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं । वे उन में काम करते हैं और अलग से अपना बिजिनेस चलाते हैं । वहां पर उन की एक एक साल तक हाजिरी लगती है । पैसा सरकार का होता है और काम उधर होता है । मैं अर्ज करूंगा कि यह जो भ्रष्टाचार है उस को रोका जाय । जब तक यह भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक कोई बात ठीक नहीं हो सकती है । जब बड़े लोग भ्रष्टाचार कर के छोटे काम करते हैं तो फिर छोटे लोगों में, आम जनता में एक भ्रम पैदा हो जाता है । जिस तरह से यह कहा गया है कि :

"चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय,
दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय ।"

कल्चर और साइंटिफिक रिसर्च, इन दो पाटों में आ कर कोई भ्रष्टाचार से साबित बचा हुआ कोई नजर नहीं आता । इसलिये इस सारी चीज़ को रिव्यू किया जाय ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तालीम का काम दो हिस्सों में बंटा हुआ है । १३ भाषाओं के इन्चार्ज हैं श्री हुमायून् कबिर और हिन्दी भाषा जो है उस के इन्चार्ज हैं हमारे मिनिस्टर आफ एजुकेशन । जितने तरह की टैकनिकल तालीमें हैं उन के इन्चार्ज हैं श्री हुमायून् कबिर और जो दूसरी यूनिवर्सिटियां वगैरह हैं उन के इन्चार्ज हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब । एक हंडिया के अन्दर दो पेट हैं । एक में रबड़ी पकती है और एक में खीर । अधिकारों को भी बांट दिया, और उन की तरक्की को भी बांट दिया । मैं चाहूंगा कि ये दोनों इकट्ठे किए जायें जिस से कि तरक्की हो सके ।

इस के बाद मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा । ३४ करोड़ की रकम खर्च होती है । हम समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद का नक्सा सामने रखते हैं । एक तरफ आप देखें कि बड़ी

[श्री बागड़ी]

बड़ी तनखाहें हैं और बड़ी बड़ी सहूलियात हैं, जिनका अगर हिसाब लगाया जाय तो एक एक आदमी पर कई हजार आ जाता है, और दूसरी तरफ छोटी तनखाहों को देखिए और जो उन लोगों को सहूलियतें मिलती हैं उन को देखिये तो आप को पता चलेगा कि उन का जीवन दूभर हो रहा है। आप को इन तनखाहों और सहूलियतों में एक और सौ का अन्तर मिलेगा सरकार के मुहकमों में। तो इस प्रकार सरकार बराबरी नहीं ला सकपी बल्कि नाबराबरी की खाई को और मजबूत बनाती जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सदन इस बात को सोचे और माननीय मिनिस्टर महोदय इस की तरफ खास तौर से ध्यान दें, और देखना चाहें तो मुझ से ले सकते हैं और इस की पड़ताल कर सकते हैं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा प्रोफेसर हुमायून् कबीर जी का, जोकि भारत के अग्रगण्य विद्वानों में से एक हैं, एक खास विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस में कोई सन्देह नहीं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और महत्वपूर्ण खोज करता है। खोज जितनी भी की जाय उतनी ही अच्छी है। इस से भारत वर्ष के लुप्त इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है इसलिए मैं एक विशेष विषय की ही ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आकाश में भ्रमण करने के विमान आदि के बारे में आज यह कहा जाता है कि यह बाहर से आया है। लेकिन ऋग्वेद के मंत्र २, सूक्त ३४ और मंडल एक में कहा गया है:

त्रि नक्तं याथास्त्रि रश्विना दिवा

महर्षि दयानन्द ने इस का भाष्य किया है कि २४ घंटे के अन्दर, १२ घंटे दिन के और १२ घंटे रात के, सारे ब्रह्मांड के तीन चक्कर कर सकता है, आकाश का विमान भी, समुद्र का यान भी और भूमि पर चलने वाला यान भी। बाहर से इन चीजों को लाने पर आप बहुत रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मैं इस ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप संस्कृत के ग्रन्थों की भी खोज कराइए तो आप को अनेक बातों का जो अपने यहां थीं पता चलेगा।

एक उदाहरण और है। कहा जाता है कि न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का पता लगाया। लेकिन यह बात गलत है। यहां प्राचीन साहित्य में सब कुछ है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और योग दर्शन तीन विज्ञान के ग्रन्थ हैं हमारे यहां, उन में लिखा है अणु के बारे में:

परं वात्रुटेः

संस्कृत ग्रन्थों में अणु उस को कहा गया है जोकि अन्तिम टुकड़ा होता है और जिस के आगे टुकड़े नहीं हो सकते। उस का लक्षण यह है:

धारणाकर्षणोपपत्तेश्च

उस के दो धर्म हैं, एक धर्म है धारण करना और दूसरा धर्म है आकर्षण करना। यह अणु का धर्म है। एक अणु दूसरे को धारण करता है और दूसरे को आकर्षण करता है। पृथ्वी में भी यही धर्म होगा, जल में भी होगा, अग्नि में भी होगा और वायु में भी होगा। चारों प्रकार के परमाणुओं में यह चीज है। न्यूटन ने एक फल को गिरते हुए देख कर केवल पृथ्वी पर विचार किया। हमारे वैशेषिक

दर्शन के भाष्य में लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ की जो प्रकृति होती है, जो उस का मूल है उधर ही जाता है। पृथ्वी पृथ्वी की तरफ जायगी, जल जो ऊपर से गिरता है तो वह पृथ्वी के नीचे जायगा जहां उस का स्थान है, अग्नि नीचे नहीं जायगी क्योंकि उस में भार नहीं है, इसलिए वह आकाश में गमन करेगी। वायु बीच में बराबर रहता है। तो वायु के द्वारा और सूर्य के द्वारा जितने लोक लोकान्तर हैं, जितना ब्रह्मांड है उन सब का धारण और आकर्षण किया जाता है। यजुर्वेद के अध्याय ३३ मंत्र ४३ में कहा है :

आकृषणेन रजसा वर्तमानः सविता देवो याति भुवनानि पश्यन्

न मालूम न्यूटन को कहां से ले आए ये पाश्चात्य विद्वानों की जूठन खाने वाले लोग। अपने ग्रन्थों में सब कुछ लिखा हुआ है। हमें इस की खोज करनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से नम्र प्रार्थना करूंगा कि संस्कृत के ग्रन्थों की खोज कराने का विशेष यत्न करें। उस में यह चीजें मिलेंगी।

मैं निवेदन करूं कि आप का महकमा काफी काम कर रहा है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता। जिस ने जो काम किया है उस का अहसान मानूंगा, जो नहीं करता है उस को छोड़ता हूं। मैं निवेदन करूं कि अभी हाल में खुदाई में झज्जर गुरुकुल के आचार्य पूज्य ब्रह्मचारी श्री भगवान् देव जी को यौधेय काल के सिक्के मिले हैं। यौधेय वे लोग थे जिन्हों ने महाभारत काल में अर्जुन से १८ बार युद्ध किया था, तो उन के सिक्के उन के पास हैं, कुषाण वंश के सिक्के उन के पास मौजूद हैं और बाद के मुगल काल के भी सिक्के उन के पास हैं।

अभी दो तीन दिन हुए एक विद्वान् ने दिल्ली में भाषण किया था। उस में उन्हों ने बताया कि यह जो कुतुबमीनार है इस को कुतुब ने नहीं बनवाया था, यह विष्णु ध्वज है। जो लोहे की लाट लगी है उस में संस्कृत और प्राकृत में लिखा है कि इस मीनार को संस्कृत काल में समुद्र गुप्त के पुत्र ने बनवाया था। यह खोज हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि इस को अन्तिम इत्थम् न मान लें पर इस को खोज तो कराएं।। और जिन लोगों ने इस प्रकार की खोजें की हैं, जैसे श्री आचार्य भगवान् देवजी, उन लोगों को अपने सम्पर्क में लीजिए और उन को सहयोग दीजिए। वे बड़ी खोज कर रहे हैं और इस खोज के आधार पर भारत का इतिहास बनेगा।

आप की अधीनता में एक इतिहास निकला है जिस का अभी पहला भाग छपा है, दूसरा छपने वाला है और तीसरा भाग आगे आवेगा। तो उस पहले भाग में लिखा है कि सिद्धान्त कौमुदी का बनाने वाला पाणिनी है। यह कितनी भद्दी भूल है, संस्कृत का एक छोटे से छोटा विद्यार्थी ऐसी भूल नहीं कर सकता, पर इस इतिहास में यह लिखा है। तो मेरा निवेदन है कि इस काम में योग्य विद्वानों को लगाइए जोकि इस विषय में पारंगत हों, यह नहीं होना चाहिए कि जो आप की मिनिस्ट्री में सरविस के लोग हैं उन को ही इस काम पर लगा दिया जाय। जो इस विषय के विद्वान हों उन को इस काम पर लगाया जाय। जब उन का उस तरफ ध्यान दिलाया गया तो उन्हों ने कहा कि सिद्धान्त कौमुदी और अष्टध्यायी पाणिनि की बनाई हुई हैं। सिद्धान्त कौमुदी वास्तव में भट्टोजिदीक्षित की बनाई हुई है जिस को थोड़ा समय हुआ और पाणिनि तो बहुत पहले हुए थे। हमारे पास इस का प्रमाण है।

अल्पावशिष्टे तु कृते युगे।

हमारे सूर्य सिद्धान्त के ग्रन्थ को बने हुए २१ लाख ६५ हजार वर्ष हो गए हैं। यह खोज करने की चीज है। इस ग्रन्थ में सूर्य का, चन्द्रमा का और पृथ्वी का जितना भी बोध होता है वह २१ लाख ६५ हजार वर्ष पुराना है, इधर का नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य सिद्धान्त २१ लाख ६५

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

हजार वर्ष पहले बनाया गया था। इस की खोज कराई जाय तो बहुत सी बातों का आप को पता चलेगा। जो अनेक सिद्धान्त पाश्चात्य जगत में चल रहे हैं वे आप को अपने ग्रन्थों में मिल सकते हैं।

योग दर्शन एक छोटा सा दर्शन है। यह संस्कृत का अद्भुत ग्रन्थ है। इस को महर्षि पातंजलि ने बनाया था और इस की टीका महर्षि व्यास ने की है। उन्हों ने उस में कहा है कि मनुष्य प्राणायाम के बल से आकाश में गमन कर सकता है। मैं कहता हूं कि आप इन बातों को सत्य न मानिए लेकिन इन की खोज तो कराइए, खोज करने से आप को पता चलेगा।

इसी भांति वैशेषिक दर्शन है जिस को कणादि ऋषि ने बनाया था। उनका नाम कणादि इसलिए पड़ा था कि उन्होंने कण कण को बीन लिया था, उन्होंने एक एक अणु को छान लिया था। महर्षि गौतम का नाम अक्षपाद था। उन के पैरों में आंखें नहीं थीं लेकिन दुनिया भर के विद्वान् आ कर उन के चरणों में सिर झुकाते थे। कणादि बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे बल्कि जंगलों में झोंपड़ी में रहते थे। और जिस समय किसान खेत काट लेता था और बीनने वाले शिला भी बीन ले जाते थे, उस समय जो दाना खड़ में पड़ा रह जाता था उस को उठा कर कणादि खाते थे। उन्हों ने संसार को वैशेषिक दर्शन जैसा ग्रन्थ दिया। तो उस में वेद से आगे की भी बहुत सी चीजें लिखी हैं और बताया गया है कि एक अणु कैसे फोड़ा जा सकता है। उस में सूर्य की महत्ता के बारे में भी लिखा है। उस में लिखा है कि सूर्य से भी बलवान वायु है। पृथ्वी के अन्दर चार धर्म हैं। परन्तु जल उस से भी सूक्ष्म है, अग्नि जल से भी सूक्ष्म है और वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है। तो इस प्रकार संसार चार प्रकार के परमाणुओं से बना है, पार्थिव, आप्य, तैजस और वायवीय। इस रचना के बारे में खोज कर के उसे आप को संसार के विद्वानों को देना चाहिए। और इस कार्य के लिए आपको संस्कृत के ग्रन्थों की खोज करवानी चाहिए। हमारे देश में संस्कृत के बड़े बड़े अच्छे विद्वान् हैं, हमारे दक्षिण भारत में संस्कृत के विद्वान् हैं और बंगाल में हैं। दुर्भाग्य से वे अंग्रेजी के भी विद्वान् हैं : उनसे सहायता लीजिए। दुर्भाग्य, मैं ने इसलिए कहा कि उन पर आंग्ल भाषा का दुष्प्रभाव पड़ता है तो वह भी हमारी जो प्राचीन वैज्ञानिक संस्कृति थी उस को वह भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाऊं कि एक शब्द "विष" है। अब 'विष' का जब हम उन से अर्थ पूछते हैं तो इसका अर्थ वे जहर, "पौयज़न" करते हैं। लेकिन मैं उन इंगलिश वालों से यह पूछना चाहता हूं कि इस पौयजन का क्या अर्थ है, रूट मीनिंग क्या है तो वे चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर संस्कृत वाले से यही प्रश्न किया जाय कि भाई विष का रूट मीनिंग क्या है तो वह झट से बतला देगा कि विष-विप्रयोगे। विष धातु विप्रयोग अर्थ में है। विष धातु विरुद्ध प्रयोग में आता है। नाजायज़ इस्तेमाल ही विष है। घी, दूध व अन्न का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाय तो वह विष बन जाता है। अगर संखिया का जायज़ इस्तेमाल किया जाय तो वह अमृत बन जाता है। यह महत्ता संस्कृत में ही है कि वह सारी चीज़ों को मूल रूप में बतला देती है।

संस्कृत में थोड़े थोड़े पृष्ठों के काफी अच्छे ग्रंथ उपलब्ध हैं। छहों दर्शन के अगर संस्कृत के मूल ग्रंथ लिये जायं तो वह लगभग तीन, चार रुपये में आ जायंगे। इसी तरह भारद्वाज मुनि का विमान शास्त्र बनाया हुआ है। उस की व्याख्या स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने की है जो कि प्रकाशित हो गई ह। वह गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को भेजी गई है। मैं समझता हूं कि आप के मंत्रालय में भी आ गयी होगी। यदि नहीं आई है तो उस को मंगवा कर देखें।

भारद्वाज मुनि ने विमान के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारे यहां पहले पैट्रोल से यह चीज नहीं चलती थीं। हमारे यहां पहले विमानों में पारे का प्रयोग किया जाता था। अब पारे की विशेषता यह है कि विमान जब चलता है तो पारा वाष्प के रूप में हो

जाता है और भूमि पर उतरने पर ठंडा पड़ कर वह वाष्प फिर पारे के रुप में आ जाता है। यह चीजें सामान्य जनता के काम के लिए नहीं आती थीं बल्कि राष्ट्र के लिए राज्य शासन के लिए काम में ली जाती थीं। शत्रुओं से अपने देश को बचाने के लिए और संसार में खोज करने के लिए भ्रमण करने में यह विमान काम में लाये जाते थे।

सब से पहले इतिहास को महाभारत यह बतलाता है कि "त्रिविष्टप" जिसको कि आज तिब्बत कहते हैं दरअसल यह भारत की पवित्र भूमि है, यहां राजा उपरिचर यह विमान लेकर हिमालय पर्वत में चारों दिशाओं में घूमा और यह देश चूंकि सबसे अच्छा मालूम पड़ा तो आर्यों ने इसे बसाया। इसलिए इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है इस से पहले कोई नाम नहीं रहा है। यह कहना कि यहां पहले आदिवासी बसते थे बिल्कुल झूठ है। इसलिए आदिवासी नाम बिल्कुल ग़लत नाम है। यूरोपियन इतिहासकारों द्वारा इस तरह की बात कह कर जनता में भ्रामक धारणाएं पैदा करने की कोशिश की जाती है। यह भूमि सब से पहले आर्यों ने ही बसाई और इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। इससे पहले इस देश का और कोई नाम नहीं था। प्राचीन इतिहास की खोज कर देख ल इससे पहले और कोई नाम नहीं था। मुझे आशा है कि यह मंत्रालय इन बातों की खोज करायेगा ताकि असली तथ्य देश की जनता के सामने आ सके। धन्यवाद।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : हम वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में यह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय एक दूसरे के कार्य के अनुपूरक हैं। केवल प्रशासनिक कारणों से ही इन्ह पृथक रखा गया हैं।

इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में गवेषणा करना है। इस कार्य के लिये खुदाई का कार्य, प्राचीन मूल पुस्तकों का प्रकाशन आदि किया जाता है। हमें यह जानने की अत्यन्त आवश्यकता है कि पुरानी संस्कृति किस प्रकार की थी।

इस संबंध में सभा के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। पुराणों को पढ़ने से प्रतीत होगा कि देवों और असुरों के बीच युद्ध विन्ध्याचल-क्षेत्र में हुए थे। बाली का राज्य भी वहीं था। हैहय राज्य भी वहीं था। किन्तु अभी उस क्षेत्र में खुदाई करने के विषय में स्थान निश्चित करने के सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया गया है।

मंत्रालय का दूसरा कार्य पुरानी मूल पुस्तकों का प्रकाशन है जो हमारी प्राचीन संस्कृत और जीवन पर प्रकाश डाल सके। पूना में वैदिक संशोधन मंडल है जो वैदिक साहित्य के संबंध में गवेषणा और अनुसंधान का कार्य करता है। इसने सायण भास्य सहित, ऋगवेद को प्रकाशित किया है। श्रोता कोश के भी कुछ खंड प्रकाशित किये जा चुके हैं और बाकी तैयार किये जा रहे हैं।

यह वेदों के अलावा अन्य विषयों पर भी गवेषणा कर रहा है। पारसियों की एक बाइबिल है अवेस्ता। यह केवल हीब्रू लिपि में ही प्रकाशित हुई थी। कभी यह रोमन लिपि में भी प्रकाशित हुई थी। इसलिये भारतीयों को इसे या तो रोमन या हीब्रू में ही पढ़ना पड़ता है। किन्तु हम अब इसे देव नागिरी में प्रकाशित कर रहे हैं। इसका पहला भाग प्रकाशित किया जा चुका है।

इस संस्था के उद्देश्य महान हैं। यह देश की विभिन्न संस्कृतियों में एक सूत्रता लाने का प्रयत्न कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

इस संस्था के प्रति उदारता और प्रशंसा की भावना बनाये रखनी चाहिए । देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की संस्थायें हैं, जैसे पारदी और होशियारपुर में, जो वेदों के प्रचार संबंधी कार्य कर रही हैं, अतः मेरा सुझाव है कि इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । कुछ पश्चिम पंडितों द्वारा वेदों का अध्ययन किया गया था, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि हम फिर से वेदों को अपने दृष्टिकोण से देखें और जनता को बताय कि इन में क्या कुछ कहा गया है ।

यदि हम विकास करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने पूर्वजों के विचारों को सम्मुख रख । वेदों का अध्ययन इस कारण और भी आवश्यक है ।

इंडिया आफिस लाईब्रेरी, लन्दन, के बारे में भी कोई सन्तोषजनक निश्चय पर पहुंचा जाना चाहिए । जहां अन्य मामलों पर भारत-पाक वार्ता चल रही है इस मामले को भी शीघ्र ले कर पुस्तकालय को भारत में लाना चाहिए, जो कि इस का उचित स्थान है ।

यह सूचना उपलब्ध की गई है कि ६६० विद्यार्थियों को विदेशों में भेजा गया है, परन्तु यह भी बताया जाना चाहिए था कि उन्हें किस उद्देश्य से भेजा गया है, आदि, आदि ।

एक अन्य सुझाव मैं आप को दूंगा । मैं ने अपने राज्य की विवरणिका को देखा है, विशेषतया कोल्हापुर, वारधा और जलगांव जिलों के संबंध में । मैं समझता हूं कि यह काम उन लोगों के सपुर्द किया गया है जो इतिहास के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं । इन पुस्तकों में ऐसी सूचना होनी चाहिए जिस के बारे में चुनौती न दी जा सके । मेरे ख्याल में एक अन्य समिति नियुक्त कर के उन पर गम्भीरतापूर्वक सोच विचार करके ही इन्हें प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं उन सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने, पक्ष में अथवा विपक्ष में, इस वाद-विवाद में भाग लिया । शायद कुछ सदस्यों ने कटु आलोचना भी की, परन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत कम थी । ऐसा केवल एक ही सदस्य था जिस की आलोचना न्यायोचित सीमा से भी आगे बढ़ गई थी ।

मैं एक एक करके सभी उठाये गये प्रश्नों को लूंगा । इन को मुख्यतया तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: राष्ट्रीय प्रयोगशालायें, तकनीकी शिक्षा विभाग और सांस्कृतिक कार्य । श्री कार, जिन्होंने चर्चा आरम्भ की, ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तकनीकी शिक्षा संबंधी कार्यों की योजना शांति-काल के लिये तैयार की गई थी परन्तु इसे आपात की आवश्यकतानुसार कार्य करना पड़ा । मैं समझता हूं कि यह योजना के प्रति श्रद्धांजलि है कि इस द्वारा आपातकाल सबंधी सभी मांगों को पूरा किया गया । यद्यपि हमारे समक्ष अभूतपूर्व मांग रखी गईं परन्तु फिर भी, तकनीकी शिक्षा के क्षत्र में, मैं समझता हू कि वर्तमान सुविधाओं से ही हम ने उन्हें अधिकतर पूरा किया । गत पांच अथवा छः वर्षों में हुए विस्तार के फलस्वरुप देश में काफी सुधार हुआ है । द्वितीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवशों की सख्या लगभग ५००० से ६००० थी । इस वर्ष १९६२ में, इन प्रवेशों की संख्या १७,६०० हो गई है । आप समझ सकते हैं कि किस गति से विकास हुआ है । हम, यथासम्भव, अतिरिक्त व्यय के बगैर ही सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई सदस्यों ने इस बात की ओर निर्देश किया कि इस मंत्रालय के आयव्ययक में कमी कर दी गई है। इस वर्ष हमने लगभग ३ से ४ करोड़ रुपये की बचत की है, और आगामी वर्ष में भी इस राशि की बचत की जायेगी। उन्होंने ठीक ही कहा कि आपातकाल में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीकी शिक्षा कार्य के बजट में वृद्धि होनी चाहिये थी। जहां तक तकनीकी शिक्षा का संबंध है, इस के बजट में कोई कमी नहीं की गई है। बल्कि इसमें कुछ वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में भी, यद्यपि आरम्भ में कुछ कमी की गई है, हम बातचीत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन उपलब्ध किया जायगा।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे विश्वास है कि धन की कमी के कारण देश के वैज्ञानिक विकास अथवा तकनीकी शिक्षा विकास कार्यों में बाधा नहीं पड़ने दी जायगी। बेशक हम अनुभव से सीखने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक बार जब एक प्रयोगशाला के लिये योजना बनाई जाती है अथवा एक इंजीनियरिंग कालेज के लिये योजना बनाई जाती है हम कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिये, गत कुछ वर्षों के अनुभवों के परिणामस्वरूप, हम आशा करते हैं कि इन विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपलब्ध धन को गत वर्षों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में ला सकेंगे।

श्री प्रभात कार ने एक शिकायत की जिस की चर्चा बहुत से अन्य सदस्यों ने भी की कि प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह तैयार नहीं किया जाता जब एक वैज्ञानिक एक प्रक्रिया को आरम्भ करता है तो उसका व्योरा तैयार नहीं होता। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि वैज्ञानिक को केवल तब तक ही काम छोड़ने नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि वह एक प्रक्रिया का आविष्कार न करले, बल्कि उसे औद्योगिक प्रक्रिया को पूरा करने पर भी बाध्य किया जाय जब तक कि यह उत्पादन के लिय तैयार न हो जाय? मुझे भय है कि यह आखिरी मांग स्वीकार करने योग्य नहीं है। संसार में कोई भी एक वैज्ञानिक को ऐसा करने पर बाध्य नहीं कर सकता; और जब भी किसी औद्योगिक प्रक्रिया को तैयार करना होता है तो उस पर वैज्ञानिक प्रयोगशालायें कार्य करती हैं, और अग्रिम संयंत्र भी हैं। अग्रिम संयंत्रों के पश्चात्, जब औद्योगिक उत्पादन का प्रश्न आता है तो अन्य देशों में परामर्श इंजीनियर्स और कई अन्य विशेषज्ञ होते हैं, जोकि कभी कभी निजी सार्थ और कभी कभी अन्य संगठन भी होते हैं। यह आशा करना कि एक वैज्ञानिक जिसने एक समस्या का सैद्धांतिक हल निकाल लिया है उसे उसकी टेकनालाजीकल, इंजीनियरिंग और कैमिकल इंजीनियरिंग समस्याओं का हल निकालने के लिये कहा जाना चाहिये, यह मांग असंभव है। निस्सन्देह हम इस बारे में सतर्क हैं कि प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली में सुधार होना चाहिये। इस संबंध में, यदि आप प्रतिवेदन को देखें तो विदित होगा कि गत एक अथवा दो वर्षों में हमने विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अग्रिम संयंत्रों के विकास पर बहुत अधिक बल दिया है। प्रतिवेदन में एक सूची दी गई है जिसमें आप विभिन्न अग्रिम संयंत्रों का वर्णन पायेंगे। इन अग्रिम संयंत्रों द्वारा वैज्ञानिक कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है और लगभग अर्द्ध वाणिज्यिक प्रक्रम तक ले जाया जाता है, ताकि उद्योग के लिये इन प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना आसान रहे।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि यद्यपि व्यक्त की गई आशंकाओं में कुछ सच्चाई है फिर भी उन्हें कभी कभी विस्तृत रूप दिया गया। अब हम अग्रेतर विकास के बारे में सोच रहे हैं। आज सुबह ही इस बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान बोर्ड में चर्चा हो रही थी और इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि प्रत्येक प्रयोगशाला में पाये जाने वाले "डिजाईन" विभाग के अतिरिक्त, एक केन्द्रीय एकक महानिर्देशक के साथ संलग्न होगा जो इन मामलों में परामर्श दे। इसे कार्य

[श्री हुमायून् कबिर]

रूप किस प्रकार दिया जायगा, यह सब अभी विचाराधीन है। हम इस बारे में बिल्कुल सतर्क हैं कि जब तक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को ठोस रूप नहीं दिया जाता, इंजीनियरिंग और कैमिकल इंजीनियरिंग योजनाओं को तुरन्त ही कार्य रूप देना कठिन है, इस चुनौती का सामना करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

प्रोफेसर देदीजेर और प्रोफसर ब्लैकेट की यात्रा की ओर निर्देश किया गया। वह सब बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जबकि हमें अपने वैज्ञानिकों को और अपनी प्रयोगशालाओं को स्वयं अपने स्तरों के अनुसार ही देखना है, और इस विषय में केवल बाहर के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कथनों की ओर नहीं जाना है। हम सदैव उन की सहभागिता का स्वागत करते हैं, और उन के परामर्श को महत्व देते हैं। वास्तव में प्रोफैसर ब्लैकेट हमारे ही निमंत्रण पर यहां आये थे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब प्रोफैसर ब्लैकेट को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कार्यों का पुर्नविलोकन करने के लिये बुलाया गया था तो ऐसी बात नहीं थी कि किन्हीं त्रुटियों की मालूम करने के लिये प्रशासनिक जांच कराई गई हो। उनको केवल इस प्रयोगशाला के कार्यों के पुर्नविलोकन के लिये बुलाया गया था और उन्हें इस बारे में सुझाव देने थे कि गत १० वर्षों के अनुभव के आधार पर किस प्रकार सुधार लाये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रोफैसर ब्लैकेट द्वारा अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में किये जा रहे कार्यों की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। तीन अथवा चार विभागों के विषय में उन्होंने कहा है कि इन के कार्यों की तुलना संसार के किसी भी अन्य भाग में किये जाने वाले कार्यों से की जा सकती है। उन के आलोचनात्मक दृष्टि से किये गये पुर्नविलोकन के फलस्वरूप यह स्वाभाविक है कि कहीं प्रशंसा की जाय और कहीं आलोचना की जाय, और कुछ परिवर्तनों के लिये सुझाव भी दिये जायें। हमें उनके पुर्नविलोकन को पूर्ण रूप में देखना है। इसलिये, कोई भी ऐसा सुझाव, कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की निन्दा की गई है अथवा इसमें आधार रूप से कोई त्रुटि पाई जाती है, सर्वथा गलत होगा।

कुछ समय से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कोई निर्देशक नहीं रहा है, इस तथ्य की ओर भी निर्देश किया गया। यह बात सच है, किन्तु इस का मुख्य कारण यह है कि जिन लोगों को इस पद के संभालने के लिये बुलाया गया वह किसी एक अथवा दूसरे कारणवश इसे संभालने को तैयार नहीं थे। मैं महसूस करता हूं कि किसी अनोपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने की बजाय यह अधिक अच्छा है कि किसी उपयुक्त व्यक्ति के मिलने तक प्रतीक्षा की जाय और इस बीच में एक उपनिर्देशक को भारसाधक बनाया जाय। बहुत सी अन्य प्रयोगशालाओं में हमने तुलनात्मक दृष्टि से कम आयु के उपनिर्देशकों को नियुक्त किया है ताकि वह प्रयोगशालाओं में अधिक समय तक रह सकें। मैं महसूस करता हूं कि देश में वैज्ञानिक क्षमता रखने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का यह अच्छा तरीका है कि कम आयु के लोगों को अवसर दिया जाय बजाय इसके कि सदैव प्रसिद्ध लोगों को ढूंढा जाय और उन्हें निर्देशक के पद पर नियुक्त किया जाय।

श्री प्रभात कार ने औजारों के देश में निर्माण संबंधी प्रश्न की ओर भी निर्देश किया। यह प्रश्न भी हमारे विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि सभा को ज्ञात है कि एक वैज्ञानिक औजार संगठन स्थापित किया गया है। और हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि प्रोफैसर गिल को इस संगठन का निर्देशक नियुक्त किया जाय। इस समय इस के भारसाधक प्रोफैसर माथुर हैं। दोनों ने स्विटजरलैंड की सहकारिता से कार्य को आगे बढ़ाया है। हम आशा करते हैं कि यह प्रयोगशाला वैज्ञानिक औजारों के निर्माण में और देश की एक आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि वैज्ञानिकों से केवल विज्ञान संबंधी काय करवाया जाय और प्रशासन संबंधी कार्य उन से बिलकुल न करवाया जाय। इसके लिये वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं; बहुत से वैज्ञानिक किसी अन्य व्यक्ति के अधीन रह कर काम करना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि कभी कभी प्रशासन के मामले में उनका नियंत्रण भी होना चाहिये। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों की अनुसंधान कार्य में सच्ची दिलचस्पी है। परन्तु, साथ ही साथ, भारसाधक लोगों को विज्ञान संबंधी पृष्ठभूमि से भी परिचित होना चाहिये और दोनों में सहकारिता की भावना होनी चाहिये। मुझे न तो वैज्ञानिक के और न प्रशासक के विरुद्ध कुछ कहना है। वास्तव में हम देश में विज्ञान कार्य को इन दोनों के माध्यम द्वारा करना चाहते हैं, और प्रशासक एवं वैज्ञानिक में उचित सहयोग और सहकारिता ही से विज्ञान संबंधी कार्य में प्रगति करनी संभव है। हमें यह बताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये कि इन दोनों में संघर्ष है, और कई बार संघर्ष के सुझाव मात्र से वास्तव में संघर्ष उत्पन्न हो जाता क्यों के इससे कई विचार उन लोगों के दिलों में उठ खड़े होंगे जिनका अवसर उन्हें पूर्व में न मिल पाया हो।

इसी प्रसंग में, एक वैज्ञानिक का उल्लेख किया गया जो कि ११० समितियों से सम्बद्ध थे। वह इन समितियों से किसी समय सम्बद्ध थे, अब नहीं हैं। बजाये इसके कि ऐसी प्रथा को समाप्त करने पर मंत्रालय को सम्मानित किया जाय, इस प्रश्न को फिर उठाया गया है। इस प्रकार की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, और भविष्य में इस प्रकार का अवसर ही नहीं आयेगा। जो बात चार अथवा पांच वर्ष पहले हो चुकी है और जिसका वर्णन मैं दो अथवा तीन वर्ष पहले कर चुका हूं उसे फिर से उठाये जाने का अर्थ यही निकाला जा सकता है कि या तो श्री हेम बरुआ की स्मरण शक्ति इस प्रकार की है कि जो बात एक बार उसमें आ जाये वह बाहर निकल नहीं सकती या मैं यह कह सकता हूं कि वह एक पहलू की ओर ध्यान देते हुये शेष सभी पहलुओं की उपेक्षा करते हैं।

श्री कार ने इंजीनियरिंग कालेजों पर रोक लगाने के विषय का भी उल्लेख किया। इस प्रकार की कोई रोक नहीं है। वर्ष १९६३–६४ के लिये हमने निश्चय किया है कि कोई नये इंजीनियरिंग कालेज न खोले जायें, क्योंकि हम चालू वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा कर सके हैं। मेरे माननीय मित्र को विदित है कि इंजीनियरिंग शिक्षा के मार्ग में इस समय दो कठिनाइयां हैं शिक्षकों की अनुपलब्धता और सामान की कमी। हम राज्य सरकारों पर बहुत समय से बल दे रहे हैं कि उनके वेतनों में इस सीमा तक वृद्धि कर दी जाय कि सर्वोच्च प्रकार के लोग आकर्षित हों और कालेजों में रहना पसन्द करें। मैं यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूं कि लगभग तीन वर्षों के प्रयास के पश्चात् लगभग सभी राज्यों ने सामान्यतया ऐसा कर दिया है। शायद एक या दो राज्य हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया, परन्तु मुझे पूर्ण आशा है कि वह भी अन्य राज्यों से मिल जायेंगे। इसके परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग शिक्षकों सम्बन्धी कमी को पूरा किया जा चुका है। इस कमी को पूर्ण रूप में दूर नहीं किया जा सका, इसीलिये हमने बेहतर समझा कि चालू वर्ष में पहले से आरम्भ किये गये कालेजों को समेकित किया जाये।

दूसरी कमी सामान की है। विदेशी मुद्रा की दुर्लभता की दृष्टि से नये कालेजों के लिये सामान उपलब्ध करने में कठिनाई पेश आई। इसको दृष्टि में रखते हुए भी हमने सोचा कि बहतर होगा कि वर्तमान कालेजों में सुधार लाया जाय और उन में पूरा सामान उपलब्ध किया जाय। वर्ष १९६४ से, जहां भी आवश्यक हुआ, हम नये कालेज खोलने संबंधी कार्यक्रम को हाथ में लेंगे। इस बीच में, सुविधाओं म विस्तार की दृष्टि से पग उठाये गये हैं।

[श्री हुमायून् कबिर]

३,००० अतिरिक्त स्थानों की चर्चा की गई। मेरे विचार में उन माननीय सदस्यों के मन में गलतफहमी है जिन्होंने इस बात की चर्चा की। यह ३,००० अतिरिक्त स्थान, इन्जीनियरिंग कालेजों में, चालू वर्ष में नहीं बल्कि योजना की कालावधि में होंगे। हमें आशा है कि अगले वर्ष के अन्त तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इंजीनियरिंग कालेजों में, तृतीय योजना में, २०,००० स्थानों का लक्ष्य था। १७,६०० के लक्ष्य तक हम पहले ही पहुंच चुके हैं। यदि दो वर्षों में नये कालेज खोलने के बगैर ही हम ३,००० और स्थान निकाल सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि तृतीय योजना के २०,००० के लक्ष्य से भी हम आगे बढ़ जायेंगे। अगले वर्ष बेशक कुछ नये कालेज खोले जायेंगे।

यही स्थिति डिप्लोमा संस्थाओं की भी है। वर्ष १९५६–५७ में लगभग १०,००० स्थान थे। आज ३०,००० छात्रों को प्रवेश मिला है। हमारा इन पौलीटैक्निस की संख्या में और वृद्धि करने का विचार है। जहां तक पौलीटैक्निक का प्रश्न है इनके स्थापित किये जाने पर रोक नहीं लगाई गई है। वास्तव में, चालू वर्ष में, कई एक नये पौलीटैक्निक्स स्थापित किये जायेंगे।

मैं समझता हूं कि डा० मेलकोटे ने इंजीनियर्स की संस्था के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की चर्चा की। उन्हें यह जान कर हर्ष होगा कि आज से २ वर्ष पूर्व आरम्भित एक योजना के अन्तर्गत १९ केन्द्रों में ऐसी सदस्यता के लिये ३,००० अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान पौलिटैकनिक्स और इंजीनियरिंग कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है। जहां कहीं भी अन्य प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होंगी, हम उन का भी प्रयोग करेंगे। परन्तु प्रशिक्षण का स्तर न गिरे, इस का हम विशष ध्यान रखते हैं। आपात के पश्चात् बहुत प्रभाव डाला गया था कि पाठ्यक्रम में कमी की जाय। परन्तु जहां तक इंजीनियरिंग उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रश्न है, हम ने इस प्रभाव को निष्फल बना दिया है। हम ने कह दिया है कि हम इस पाठ्यक्रम में कमी नहीं करेंगे, क्योंकि पांच वर्ष का स्वीकृत पाठ्यक्रम खूब सोच विचार, सावधानी और अध्ययन के पश्चात लागू किया गया है। इस का पूरी तरह परीक्षण भी नहीं हो पाया है। इसलिये, इस प्रक्रम पर पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना एक प्रतिगामी कदम होगा। हम प्रशिक्षण स्तर को नीचा करने अथवा पाठ्यक्रम के काल में कमी करने के लिये सहमत नहीं हुए। हमने सुझाव दिया है कि आपात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चौथे और पांचवें वर्षों के विद्यार्थी अपनी छुट्टियों में कमी करके अधिक समय अध्ययन के लिये दे सकते हैं। इस प्रकार, प्रशिक्षण स्तर अथवा पाठ्यक्रम की कालावधि का बलिदान दिये बगैर, वह एक मामले में लगभग ६ मासों में पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं और दूसरे मामले में ८ अथवा ९ मासों में।

डा० मेलकोटे ने पूछा है कि प्रतिरक्षा के लिये हमने किस प्रकार की परियोजनाओं को आरम्भ किया है। मुझे खेद है, कि उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वास्तव में, प्रतिरक्षा अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि हम आंकड़े न बतायें। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि रक्षा के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में लगभग १२० से १३० विशेष परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रयोगशालायें रक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर रही हैं। उन के

द्वारा किये गये योगदान की सराहना की गई है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में यह निरन्तर ऐसे ही योगदान देती रहेगी।

डा० मेलकोटे ने देश में श्रोवरसियर्ज़ की कमी की चर्चा भी की। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं वरन् समस्त संसार में औद्योगिक विकास के एक दुर्बल पक्ष को छुआ है। अभी कल ही मैं एक अमरीकन शिक्षक से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि अमरीका में भी मध्यम-स्तर पर कर्मचारियों की कमी पाई जाती है। स्नातक इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। हमारे पास प्रवीण श्रमिक भी काफी संख्या में हैं। परन्तु हमारे देश में मध्यमवर्ती सम्पर्क की सदैव कमी रही है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गत तीन अथवा चार वर्षों से मेरी निरन्तर कोशिश रही है कि यह कमी दूर की जाय। पूर्व में पौलीटैक्निक्स और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश का अनुपात १ : १ था। आज हमारे प्रयासों के फलस्वरूप, यह अनुपात लगभग १ : २ है। मैं चाहता हूं कि यह अनुपात १ : ३ अथवा १ : ४ हो, परन्तु इस के लिये समय की आवश्यकता है। शायद, आपात के फलस्वरूप, तृतीय योजना के अन्त तक यह अनुपात १ : २ १/२ अथवा १:३ हो जाय। हम इस दिशा की ओर अग्रसर हैं। परन्तु ओवरसीयर्ज की कमी की समस्या प्रत्यक देश में है। ब्रिटेन जैसे देश में भी यह समस्या है। हम प्रयत्न करेंगे कि जहां तक सम्भव हो यह कमी दूर हो, परन्तु इस के लिये समय अवश्य लगेगा। जब तक देश का बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास न हो जाय यह समस्या पूर्ण रूप से दूर नहीं होगी, क्योंकि बहुत से ओवरसीयर्ज़ निम्न श्रेणी से ही आयेंगे। बहुत से लोग जिन्होंने प्रवीण श्रमिकों के रूप में सेवा आरम्भ की वही लोग अनुभव प्राप्त कर के ओवरसीयर बनेंगे। हम अच्छे से अच्छे परिणामों की आशा तभी कर सकते हैं जब कि शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षित व्यक्तियों और निम्न श्रेणियों से ओवरसियर स्तर तक पहुंचने वाले लोगों का समुचित सम्मिश्रण होगा।

श्री मेलकोटे तथा श्री बड़े दोनों ने आय व्ययक में कमी करने की बात कही है। मैंने यह बात स्पष्ट करने का यत्न किया है कि कभी कमी दिखाई नहीं दे रही। फिर भी हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाय। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि आपातकालीन अवस्था में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। हम इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को जिसकी सेवा का काल एक वर्ष से अधिक हो नौकरी से न हटाया जाय। यह कहना गलत है कि प्रयोगशालायें तो फजूलखर्ची का कारण बन रही हैं। इस आपात में तो प्रयोगशालाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे इस बात का भी बड़ा आश्चर्य है कि श्री बड़े को प्रोफेसर थैकर के जनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की अध्यक्षता करने पर क्यों आपत्ति है। यह गौरव एक भारतीय को प्राप्त हुआ इस पर तो अभिमान किया जाना चाहिए। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उनका सारा खर्च भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही वहन किया गया था। अतः किसी भी दृष्टि से यह बात आपत्तिजनक नहीं कही जा सकती। श्री बड़े का कहना भी गलत है कि सारी दिल्ली में २६ प्रयोगशालायें हैं। प्रयोगशालायें तो सारे देश में फैली हुई हैं। एक जम्मू तथा काश्मीर में है, एक हैदराबाद में हैं, जोरहाट में है, मद्रास में है और इस तरह सारे देश में फैली हुई हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है और दिल्ली से कुछ मील बाहर सड़क अनुसंधान संस्था है। इससे अधिक और कोई प्रयोगशाला दिल्ली में नहीं।

[श्री हुमायून् कबिर]

हमने प्रत्येक राज्य को कहा है कि वह राज्य तकनीकी बोर्ड का निर्माण करे। बहुत से राज्यों में ऐसा हुआ है और बहुत स्थानों पर होने जा रहा है। श्री सराफ ने शिकायत की है कि वैज्ञानिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है । यह भी गलत बात है बहुत से वैज्ञानिकों का वेतनक्रम ७०० से १२५० रुपये तक है। सहायक निदेशक १३०० से १६०० रुपये ले रहे हैं। और ये सब ४० से कम की अवस्था में हैं । कई तो ३० से भी कम हैं। क्या इस अवस्था में इतना वेतन प्राप्त करना, कम कहा जायेगा ? हमारे वैज्ञानिकों को अनुभव प्राप्त करने के लिये विदेशों में भी जाना ही पड़ता है । परन्तु मुझे यह खेद से कहना पड़ता है कि वैज्ञानिकों में परस्पर सहानुभूति कोई नहीं है । हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि वैज्ञानिकों को पूरा प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे लगभग ६७० अथवा ६९० विद्यार्थी विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं । ये लोग विभिन्न विषयों में अध्ययन कर रहे हैं । इनमें से कोई ५ वर्ष के बाद आता है, कोई १० के बाद तो कोई १५ वर्ष के बाद वापिस लौटता है । वैसे उन्हें वापिस तो आना ही होता है ।

लड़कियों के लिए 'पालिटैक्निक' के खोलने की बात की गयी है । मेरा निवेदन है कि २३ ऐसे 'पालिटैक्निक' लड़कियों के लिए खोले जा रहे हैं। ७ तो खोले भी जा चुके हैं, और १ अथवा २ खुलने वाले हैं। परन्तु इस दिशा में प्रयोग अभी हाल ही में किया गया है । पहिले पहिले राज्य सरकारें इस कार्य के लिए तैयार नहीं थीं । केवल मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की सरकारें ही तैयार हो पाई थीं। परन्तु अब तो सब का विचार इस प्रकार की संस्थायें स्थापित करने का है ।

तस्करता को रोका जाना चाहिये, इस बात का हम पूरा प्रयत्न करते हैं, परन्तु फिर भी हमारा देश बड़ा व्यापक है, कोई न कोई घटना हो ही जाती है। फिर भी इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि पूरा नियन्त्रण रखा जाये । एटिलिसों के बारे में निवेदन है कि जिन 'एटिलिसों' को हम ने प्रकाशित करवाया है, वे सारे संसार में सुप्रसिद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे ही एटिलिसों को पसन्द किया है। कुछ यूरोप के अन्य देशों ने भी प्रयोगार्थ हमारे एक या दो नक्शों को चुना है। हमारे पास इतनी मांग है कि इसे पूरा किया जाना कठिन हो रहा है ।

श्री हेम बरुआ ने 'इंडिया आफिस लाइब्रेरी' का प्रश्न प्रस्तुत किया है। बड़ा महत्वपूर्ण और नाजुक प्रश्न है। इस प्रश्न का उल्लेख माननीय श्री बरुआ के अतिरिक्त और भी अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि इस मामले में हम उस समय तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि भारत तथा पाकिस्तान संयुक्त रूप से ऐसा दावा न करे। श्री भट्टाचार्य ने बहुमूल्य ग्रंथों के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। उन्हें मैं अपने सामने रखूंगा। कला खरीद समिति तो काम कर रही है। सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि लाइब्रेरी के स्थानान्तरित हो जाने पर भी विद्वानों को अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इन सुविधाओं का बहुमुखी विकास किया जा सके। हमने स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के निर्माण का कार्य डा० ताराचन्द के सपुर्द किया है । विज्ञान, तकनीक तथा संस्कृति के सम्बन्ध में जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनका पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

पुस्तकों के प्रकाशन का उल्लेख किया गया है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये अनुदानों में सरकार ने पर्याप्त वृद्धि की है। चालू वर्ष में यह रकम

११ लाख रुपये है। भारत की अन्य अनेक भाषाओं की तरह राजस्थानी के विकास के लिये भी सहायता दी जा रही है। विभिन्न अकादमियों में चल रहे पक्षपात के विषय में मुझे इतना ही कहना है कि सरकार उन सब मामलों की जांच करेगी जो उनकी जानकारी में लाये गये हैं। यदि सरकार के नोटिस में भ्रष्टाचार के कुछ मामले लाये गये तो भ्रष्टाचार के किसी भी विशिष्ट मामले की जांच की जायेगी। ताज महल की मरम्मत के मामले की मैं पूरी जांच पड़ताल करूंगा।

श्री सिद्धान्ती जी ने दुर्लभ ग्रंथों की बात की है। मेरा निवेदन है कि देश में लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति है, जिसने हमारे लिये दुर्लभ दस्तावेजों के प्रकाशन का कार्यक्रम तैयार किया है और हमने यह कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। वैदिक अनुसंधान होशियारपुर और पूना की संस्था को सहायता दी गई है। जैंड अवस्था के लिये भी सहायता दी जा रही है। जहां तक हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हमारे प्रयत्न बौद्धिक पृष्ठभूमि की ओर धीरे धीरे परन्तु अनवरत रूप से बढ़ रहे हैं। हमें अपने सुन्दर भविष्य के लिये अपना गौरवपूर्ण अतीत नहीं भूलना चाहिये। अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे कर इस विशाल व्यापक देश में एकत्व की भावना का निर्माण किया जा सकता है। अभी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नगरों तक ही सीमित हैं। समय आने पर इन्हें देहातों में भी किया जायेगा।

अन्त में विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास की बात करना चाहता हूं। मेरे विचार में एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को प्रोत्साहन दे कर और इस प्रकार सभी भारतीय भाषाओं में समान भारतीय साहित्य रखा जा सकेगा। सरकार इस समय भारतीय राष्ट्रीयता की नींव मजबूत बना रही है। इस राष्ट्रीयता की हमारे हित में ही नहीं विश्व के हित में भी बहुत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८१	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय .	३४,२७,०००
८२	पुरातत्व	१,०१,६६,०००
८३	भारत का सर्वेक्षण	३,३१,१८,०००
८४	वानस्पतिक सर्वेक्षण	२५,४६,०००
८५	प्राणिकीय सर्वेक्षण	१८,२०,०००
८६	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक- कार्य . .	१६,११,१६,०००
८७	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५१,६३,०००
१३७	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	२,८१,८३,०००

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मेरे विचार में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के लिये समय कम मिला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इससे पहिले इस पर आपत्ति कर सकते थे अब कुछ नहीं हो सकता।

अणु शक्ति विभाग

वर्ष १९६३–६४ के लिए अणुशक्ति विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई : —

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०६	अणु शक्ति विभाग .	१४,४२,०००
१०७	अणु शक्ति अनुसंधान . . .	७,७९,१८,०००
१४७	अणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . .	१५,०९,२०,०००

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : अणुशक्ति विभाग ने बड़ा सराहनीय काम किया है।

यह हर्षजनक बात है कि ट्राम्बे में भारतीय टक्नीकी विशेषज्ञ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डा० भाबा का यह वक्तव्य कि तीसरा अणुशक्ति का एकक भारतीय वैज्ञानिक ही बनायेंगे।

अणुशक्ति का आर्थिक कामों के लिये भी प्रयोग करना चाहिये। देश के वे भाग विशेषकर दक्षिण के जो कि कोयला की खानों से दूर हैं और जहां बिजली नहीं पैदा की जा सकती, वहां अणुशक्ति का प्रयोग करना चाहिये। तीसरा अणुशक्ति स्टेशन जो कि दक्षिण भारत में बनाया जाएगा उसे शीघ्र बनाया जाए।

सरकार को देश में शक्ति उत्पन्न करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कोशिशों का समन्वय करना चाहिये। हमारे देश में शक्ति के रूढ़िवादी और इन से भिन्न संसाधनों में किसी प्रकार का टक्नीकी समन्वय होना चाहिये। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अणुशक्ति की परियोजनाओं का कार्यक्रम बनाने के साथ साथ हमें पहले चालू वैज्ञानिक योजनाओं के कार्यक्रम का भी तेजी से कार्यान्वयन करना चाहिये।

जहां तक ट्रावनकोर खनिज लिमिटेड (ट्रावनकोर मिनरलज़ लिमिटेड) का सम्बन्ध है यह आरोप लगाया गया था कि 'इलमेनाइट' से 'क्रोमाइट' अलग करने के लिये कोई गवेषणा भी की गई थी। इस के फलस्वरूप निर्यात को हानि पहुंची। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

चितरंजन कैंसर अस्पताल में जो काम हो रहा है उस का टाटा मैमोरियल अस्पताल और वैसी अन्य संस्थाओं में जो काम हो रहा है उस के साथ समन्वय होना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

आशा है कि 'हैल्थ फिज़िक्स' विभाग में जो काम हो रहा है उस के नतीजे हमारे उद्योगों के लिए उपलब्ध होंगे। "सहा इन्स्टीट्युट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स' अच्छी प्रकार से काम नहीं कर रही है। डा० मेघनाद सहा की मृत्यु के उपरान्त उसे सरकार से अपेक्षित ध्यान नहीं मिला है। सरकार को उस की अधिक देखभाल करनी चाहिये।

यद्यपि हम यह समाचार पढ़ रहे हैं कि चीन अणुशक्ति में प्रगति कर रहा है और अणुबम्ब बनाने के लिये प्रयत्न कर रहा है, परन्तु हमारी सरकार की यह नीति है कि हम अणुबम्ब नहीं बनायगे और अणुशक्ति का प्रयोग शान्तिमय कामों के लिये करेंगे। यह काफी अच्छा उद्देश्य है। हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोशिश करनी चाहिये कि विश्व के हमारे भाग में अणुशक्ति से रहित प्रदेश बने।

†**डा० क० ल० राव** (विजयवाड़ा) : संसार में सब से पहले कोयला इत्यादि शक्ति के साधन थे। बाद में तैल का प्रयोग किय जाने लगा। संसार की जन संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि य शक्ति के संसाधन कम हो रहे हैं। अतः अब अणुशक्ति को प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक गवेषणा कर रहे हैं। हम इन मामलों में कई देशों में पीछ थे और हमें उन से सीखना पड़ा। 'न्यूक्लीयर फिजिक्स' अभी बचपन की स्थिति में है। अतः अणुशक्ति भिाग को अभी नया अनुसन्धान करना है। हमें इस गवेषणा में अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिये, विदेशियों की सहायता पर नहीं। हमारा उद्देश्य तजरुबा प्राप्त करने और उसे अपने विकास में प्रयोग करना होना चाहिए। पहले हमें जैसा कि हम प्रताप सागर में कर रहे हैं साधारण युरेनियम के प्रयोग के लिये एक स्टशन स्थापित करना चाहियें। बाद में दूसरे स्टेशन के लिए अच्छा युरेनियम के प्रयोग के तरीके अपनाये जा सकते हैं।

अणुशक्ति के स्टेशनों के लिये स्थान चुनने के लिय बड़े दल सारे देश भर में भेजने की आवश्यकता नहीं है। स्टेशन स्थापित करने के लिये जो तीन आवश्यक बातें हैं जो क्षेत्र भी उन के अनुसार मिल सकता है वहीं स्टेशन स्थापित किया जा सकता है।

अणुशक्ति के उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार धन व्यय कर रही है, अतः यह आवश्यक है कि जो भी अणुशक्ति पैदा हो वह एक राज्य द्वारा ही प्रयोग नहीं की जानी चाहिये। ३०० या ४०० मील के अन्दर जितने राज्य आते हैं सभी को एक स्टेशन में पैदा की गई अणुशक्ति का प्रयोग करना चाहिये।

अणुशक्ति आयोग में कुछ स्थायी सदस्य होने चाहिएं तथा कुछ अस्थायी। इस का आधार उनके उत्तरदायित्व होने चाहिये। आई० सी० एस० अधिकारियों को सदस्य बनाने का कोई लाभ नहीं।

समुद्र में जहाजों को चलाने के लिये अणुशक्ति के प्रयोग के लिए भी हमें तजरुबे करने चाहिए।

हमारा ध्येय अणुशक्ति में अधिक से अधिक तजरुबा प्राप्त करना है। अतः अणु शक्ति विभाग को थरमाल प्लांट या बौयलर इत्यादि के बनाने में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये।

अन्तरिक्ष गवेषणा भिन्न काम है। यह किसी विभिन्न विभाग को सौंपा जाना चाहिये।

अणुशक्ति विभाग की प्रकाशन शाखा को अणुशक्ति सम्बन्धी पुस्तकें निकालनी चाहिये जिन को आम लोग पढ़ सकें। इस प्रकार से अणुशक्ति का ज्ञान जनता तक पहुंच जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ल० राव]

अणुशक्ति पर व्यय करने के लिए हमारे पास उतना धन नहीं है जितना इस पर व्यय किया जाना चाहिए। अतः बहुत मितव्ययता से काम लिया जाना चाहिये। गैर-टैक्नीकी कर्मचारियों पर व्यय और उत्पादन से अन्य कामों में होने वाले व्यय में मितव्ययता की जानी चाहिये।

श्री बड़े (खारगोन): अध्यक्ष महोदय, यह एटामिक इनरजी का विषय बहुत महत्व का है और यह बहुत टैक्निकल भी है। आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसको एटामिक युग कहा जाता है। आज इस युग में रूस और अमरीका दोनों ही आणविक अस्त्रों से सज्जित हैं। पर हमारा उद्देश्य इस युग में एटामिक इनरजी को केवल पीसफुल परपजेज के लिए इस्तैमाल करना है जैसा कि हाल में प्रधान मंत्री जी ने रोहतक में कहा था। मुझे इसके बारे में कुछ कहना है।

हमारे देश में चार पाच अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं। और हमको गर्व है कि डा० भावा जैसे साइंटिस्ट भारतवर्ष में हैं। उन्होंने जो शोध कार्य किया है उसके लिए में उनका अभिनन्दन करता हूं। यह बात सुनकर जनता को बड़ी प्रसन्नता है कि हम साउंडिंग राकेट छोड़ने वाले हैं। यह देखकर हमको प्रसन्नता होती है कि एटमिक इनरजी के क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं। एटमिक इनरजी कैंसर के इलाज के उपयोग में आ रही है और मनुष्य शरीर के वास्ते उसका उपयोग हो रहा है। केन्सर के लिए चित्तरंजन केसर अस्पताल खुला है जिसमें एटमिक इनर्जी से इलाज होता है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है।

जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया उस समय रूस ने कुछ मिसाइल्स उसके पास भेज दिए थे। पता नहीं कि चाइना के पास एटामिक वैपन्स है या नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसके पास नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास होते तो वह उनका उपयोग करता। मैं समझता हूं कि इस स्थिति में अपने यहां भी हमको एटामिक वैपन्स का निर्माण करना पीसफुल परपज मानना चाहिए। हम उनका निर्माण अटैक के लिए नहीं पर आत्म-रक्षा के लिए करें।

शरीर मात्रम् खलु धर्म साधनम्

देश की रक्षा के लिए जो साधन हमारे पास है उसका उपयोग करना चाहिए इस बात को एक आदिवासी भी सही समझता है। मेरा विचार है कि हमारे देश में जो अग्रगण्य माने जाते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी, उनको भी अपने इस सिद्धान्त से हटना होगा कि हम एटमिक वैपन नहीं बनाएंगे। मैं पूछता हूं कि यदि चीन ने हमारे ऊपर एटमिक वैपन्स से हमला कर दिया तो क्या उस वक्त हम रूस से या अमरीका से कहेंगे कि हमारी मदद करो। जिस प्रकार आप दूसरे माडर्न वैपन्स का निर्माण कर रहे हैं, जैसे आप ओटोमैटिक वैपन्स का निर्माण कर रहे हैं उसी प्रकार एटामिक इनरजी की रिसर्च का लाभ उठाकर हमको एटामिक वैपन्स का भी निर्माण करना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम चाहे तो आज एटामिक वैपन्स का निर्माण कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की नान एलाइनमैंट के सिद्धान्त में भी आस्था थी लेकिन परिस्थिति के अनुसार उनको उस नीति को मोड़ना पड़ा और नान-वायलेंस की नीति होते हुए भी हमको अपनी रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है।

जिस प्रकार सर्वोदय वाले अपनी शान्ति सेना लेकर जाते हैं, अगर उस तरह हम चीन के सामने शान्ति सेना लेकर जाते तो वह नष्ट हो जाती। वहां शान्ति सेना से काम नहीं चल सकता। चीनी तो कहते हैं---पावर मीन्स वार---उनका विचार है कि सावरेनटी पावर से ही हो सकती है। जब हम एटामिक वैपन्स तैयार कर सकते हैं तो क्यों न डिफेंस के लिए उनका निर्माण करें, और ऐसा करने को एटामिक इनरजी का पीसफुल परपज के लिए उपयोग मानें।

इसके साथ साथ मैं यह कहता हूं कि आज यह माना जाता है कि यू० एन० ओ० के कारण संसार में शान्ति स्थापित है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अमरीका हिरोशिमा पर एटम बम न डालता तो इतनी जल्दी दुनिया में शान्ति न आती और हिटलर का अन्त न होता। यह जो शान्ति स्थापित हुई है यह अमरीका द्वारा जापान पर एटम बम डालने से हुई है। यदि यह सत्य है तो आज हिन्दुस्तान को विचार करना चाहिए और प्रधान मंत्री साहब को विचार करना चाहिए कि हमको अपनी रक्षा के लिए एटामिक वैपस का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि सम्भव है कि चीन के पास ऐसे वैपन हों। हमको डा० भावा को इस काम में लगाना चाहिएं और इस काम को एटामिक इनरजी का पीसफुल परपजेज के लिए इस्तैमाल मानना चाहिए।

हमारे यहां कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यहां चीन राज करे या रूस राज करे। ऐसे लोग कभी नहीं कहेंगे कि हमको एटामिक वैपन बनाने चाहिएं। वह तो इस बात की प्रशसा करेंगे कि हमारा उद्देश्य एटामिक वैपन बनाना नहीं है। वे लोग तो जानते हैं कि यहां चीन का राज होगा तो अपने भाई का राज्य होगा, रूस का यहां राज्य होगा तो अपने भाई का होगा। लेकिन जो हम लोग भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाले हैं और जो चाहते हैं कि देश में डिमोक्रेसी रहनी चाहिए, उनका यही कहना है कि हमको केवल अपने डिफेंस के वास्ते एटमिक वैपन्स का निर्माण करना होगा। इसी कारण मैं कहता हूं कि इसके लिए बजट बहुत कम रखा गया है और समय भी कम दिया गया है। इस बारे में शुक्रवार को मेरा प्रस्ताव भी आने वाला है कि हमको डिफेंस के लिए एटामिक वैपन बनाने चाहिएं और उसको एटामिक इनरजी का पीसफुल परपजेज के लिए इस्तैमाल मानना चाहिए।

मेरी प्रधान मंत्री जी से विनती है कि हमारे यहां जो एटामिक रिसर्च में इतनी उन्नति हो गयी है उसका लाभ उसको उठाना चाहिए, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम चाहें तो एटामिक वैपन बना सकते हैं, तो हमें चाइना से अपनी रक्षा के लिए एटामिक वैपन अवश्य बनाना चाहिए। यही मेरी उनसे विनती है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द) : अणुबम्ब न बनाने की सरकार की नीति उचित है। ऐसे बम्ब बनाने में बहुत धन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें परीक्षण इत्यादि अपनी भूमि पर ही करने होंगे जिनसे देश को हानि होगी। अतः सरकार का निर्णय देश के हित में है।

देश में अणुशक्ति का विकास होना चाहिए, अन्यथा हम इस सम्बन्ध में संसार के अन्य देशों से पीछे रह जाएंगे।

अणुशक्ति विभाग और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में कुछ विषयों पर मतभेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

अन्तरिक्ष गवेषणा कार्यक्रम के लिए यह विभाग वधाई का पात्र है। इस सम्बन्ध में हमें वर्तमान सब प्रगतियों के बारे में जानकारी रखनी सैटेलाइट संचार नामक परियोजना जो हमारे देश में स्थापित की जा रही है वह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हम कई मित्र देशों के निकट आजाएंगे।

हमें 'इलमेनाइट' के निर्यात को बढ़ाना चाहिए।

सरकार को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि क्या तारापुर परियोजना को पूरा करने के लिए अमरीका ने पूरा उत्तरदायित्व लिया है। यदि उसका काम ठीक न हुआ तो क्या वे उसके लिए जुर्माना देंगे। राना प्रतापसागर परियोजना में जो देश सहयोग दे रहे हैं उन्हें अपने काम के बारे में आश्वासन देना चाहिए।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): हमारे वैज्ञानिकों ने जो अच्छा काम किया है उसके लिए हमें अभिमान है।

सरकार को वैज्ञानिकों से प्रशासन का काम नहीं लेना चाहिए। उन्हें सारा समय वैज्ञानिक काम के लिए प्रयोग करना चाहिए।

अणुशक्ति आयोग के खनिज विभाग के लिए पूरा समय काम करने वाला निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसकी ओर जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अणुशक्ति आयोग जैसी संस्थाओं का काम किसी वैज्ञानिक के अधीन होना चाहिए। प्रशासन के काम के लिए अलग अधिकारी होने चाहिएं। प्रशासकों और वैज्ञानिकों के कामों में समन्वय के लिए कार्यवाई करनी चाहिएं।

हमें अणु हथियार नहीं बनाने चाहिएं। अणुशक्ति शान्तिमय कामों के लिए प्रयोग में लाई जानी चाहिए। परन्तु अणु हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त करने पर हम जो धन व्यय कर रहे हैं क्या उसे और किसी काम के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदनों में अणु खनिजों की प्राप्ति के लिए किए गए काम के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए।

क्या सरकार ने वैज्ञानिकों के वेतन में वृद्धि की है। प्रधान मंत्री ने कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखते हुए वैज्ञानिकों के वेतन इत्यादि के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा। वैज्ञानिक जिस विभाग में भी काम करते हैं उन्हें वहां कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण): अणुशक्ति की गवेषणा और विकास के काम उत्साहप्रद प्रगति हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे वैज्ञानिक दूसरे न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना स्वयं करेंगे। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उस स्टेशन स्थापित करने में प्रत्येक स्तर पर हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनीयरों को स्वाधोनता होगी। इस परियोजना के कार्यान्वियन में किसी प्रकार की वित्तीय रुकावट नहीं होनी चाहिए।

जादुगुदा में युरेनियम के प्रयोग के लिए इस विभाग को अपेक्षित विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिए। युरेनियम के कारखाने में धन की न उपलब्धि होने के कारण काम को हानि पहुंचेगी। किसी समय भी विदेशी मुद्रा के कारण प्रगति में रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस संकट काल में ऐसा करना खतरनाक है।

†**डा० गायतोंडे** (गोआ, दमन और दीव) : लगभग सभी सदस्यों ने डा० भाभा के कार्य की प्रशंसा की है। ६ बर्ष के थोड़े ही समय में इस रिएक्टर ने बहुत कार्य किया है।

यह कहा गया है कि टाटा मेमोरियल हास्पिटल अणुशक्ति विभाग का है। इसका कारण यह बताया गया है कि केन्सर की चिकित्सा में रेडियो सक्रिय आइसोटाप्स का प्रयोग किया जाता है। मेरे विचार से यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण इस अस्पताल को इस विभाग के अधीन रखा जाये। यह बात भी उपहासप्रद लगती है कि आयोग गर्भ निरोध उपकरणों का भी उत्पादन करता है। हमें अणुशक्ति को अधिक महत्व देना चाहिये क्यों कि इस शक्ति की हमारी विकास परियोजनाओं और अन्य वस्तुओं के लिये बड़ी आवश्यकता है। विकसित देशों द्वारा अणु शक्ति के प्रयोग में आगे बढ़ने को, और अपनी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, हमें देश में यथा संभव शीघ्र और अणुशक्ति केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिये।

ज्ञात हुआ है कि केरल के मोनोजाइट रेत में काफी रेडियो सक्रियता है। इस बारे में कुछ कार्य किया जाए।

गोआ के रेत में भी कुछ भारी तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिये।

अब मैं अणुशक्ति संबंधी सामान्य नीति के प्रश्न को लेता हूं। निसंदेह हम अणु बम नहीं बनना चाहते हैं। तथापि सरकार को इस संबंध में नीति स्पष्ट करनी चाहिये।

इस प्रतिवेदन में दुर्घटनाओं का जिक्र नहीं है। केवल यह कहा गया है कि हम इसके रोकथाम के उपाय कर रहे हैं। तथापि मेरा सुझाव है कि आयोग को आगामी प्रतिवेदन में दुर्घटनाओं के पहलू पर प्रकाश डालना चाहिये।

इंग्लैंड में इस समय ५७५ मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, १९६८ में यह बढ़कर ५४०० मेगावाट हो जायेगा। जब कि भारत में निकट भविष्य ये केवल ३८० मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। हमें इस मामले में और आगे बढ़ना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत आइसोटाप्स के मामले में स्वावलम्बी हो गया है। अब हमें आइसोटाप्स का आयात नहीं करना पड़ता है।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परमनी) : इस विभाग ने अभी तक जो भो प्रगति की है वह उल्लेखनीय है और इसके लिये आयोग प्रशंसा का पात्र है।

हमारे जैसे कम विकसित देश में, अणुशक्ति पर ही शीघ्र आर्थिक प्रगति के लिये भरोसा किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री शिवाजी राव शं० देशमुख]

आणविक खनिज साधनों का जिस पर तारापुर अणुशक्ति केन्द्र निर्भर करेगा विदेश से आयात किया जाना है। अणुशक्ति ईंधन के लिए विदेशी संभरण पर निर्भर करना देश के हित में नहीं है। अधिकारीगण इस बात को ध्यान में रखें कि उपयुक्त समय के भीतर, अपेक्षित आणविक ईंधन का देश में ही उत्पादन हो।

राणा प्रतापसागर विद्युत केन्द्र के डिज़ायन के लिये जिसमें भारतीय अयस्क का इस्तेमाल किया जायेगा यह विभाग बधाई का पात्र है। इस समय हमारे पास केवल तीन अणुशक्ति रिएक्टर हैं यह संख्या हमारे देश के लिये अपर्याप्त है सरकार को चाहिये कि वह इनकी संख्या में वृद्धि करने की यथा शक्ति कोशिश करे केवल इसी से हमारा देश विश्व में अणुशक्ति विकास वाले देशों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है।

अणुशक्ति आयोग को यह देखना चाहिये कि भारत अणुशक्ति के शांति कालीन उपयोग के कार्य में पीछे न रहे। सरकार को चाहिये कि इस दिशा में प्रयत्नों में वृद्धि की जाये।

तारापुर बिजली घर में जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव है उनका संभावित यह नतीजा होगा कि यह केन्द्र अपने लक्ष्य के अनुसार तरक्की नहीं कर सकेगा। सरकार को यह देखना चाहिये कि कोई ऐसा कार्य न किया जाये कि जो योजना की प्रगति में बाधक हो। इस केन्द्र से महाराष्ट्र की विद्युत क्षमता बहुत बढ़ जायेगी।

भविष्य में अणुशक्ति केन्द्रों के लिये उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिये प्रविधिक आर्थिक स्तर जांच पर पड़ताल की जाये।

चीन द्वारा तिब्बत में आणविक विस्फोट किए जाने के कथित समाचारों से जनता में काफी बेचैनी फैल गयी है। सरकार को इस विषय में प्रकाश डालना चाहिये।

अंत में मैं आयोग को उसकी सफलता के लिये बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि तारापुर बिजलीघर यथासमय पूरा हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री सोमवार को चर्चा का उत्तर देंगे।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, २५ मार्च, १९६३/४ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, २३ मार्च, १९६३

२ चैत्र, १८८५ (शक)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २५१९–२२

(एक) श्री हेम बरुआ ने २१ मार्च, १९६३ को जमुरिया कोयला-खान में हुई दुर्घटना की ओर, जिसके फलस्वरूप छै मजदूरों की मृत्यु हो गई और कई अन्य मजदूरों को चोटें आई, श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री र० कि० मालवीय) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(दो) श्री यशपाल सिंह ने तिब्बत में चीनी सेनाओं के कथित भारी जमाव की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बवध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५२२

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) कृष्णा-गोदावरी के जल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य 'कृष्णा-गोदावरी आयोग की रिपोर्ट—संक्षेप और मुख्य सिफारिशें' की एक प्रति सहित।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक १६ मार्च, १९६३ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ४६२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६३ की एक प्रति।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२३

तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें २५२३–७२

(१) शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(३) अणुशक्ति विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २५ मार्च, १९६३/४ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि .

अणुशक्ति विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

विषय-सूची—जारी

श्री च० का० भट्टाचार्य	२५४९–५०
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	२५५०—५४
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	२५५४—५७
डा० मा० श्री अणे	२५५७–५८
श्री हुमायून् कबिर	२५५८–६६
अणु शक्ति विभाग	२५६६
श्री ही० ना० मुकर्जी	२५६६–६७
डा० क० ल० राव	२५६७–६८
श्री बड़े	२५६८–६९
श्री विद्याचरण शुक्ल	२५६९–७०
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	२५७०
श्री व० ब० गांधी	२५७०–७१
डा० गायतोंडे	२५७१
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	२५७१–७२
दैनिक संक्षेपिका	२५७३

PLS. 41. XV. 26. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।